सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 88 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 10 जनवरी 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

17 जनवरी को चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी से चलेगी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में करेंगे। यह ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। रेल मंत्री के मुताबिक 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएंगी। इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएंगी।

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे में 2026 में एक बड़ा बदलाव होगा। सभी तरह के सुधारों पर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शामिल है। रेलवे में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने एक नया स्ट्रक्चरल तरीका अपनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक नया स्ट्रक्चरल तरीका पेश किया जाएगा, ताकि भारत के स्टार्टअप और इनोवेटिव दिमाग रेलवे से जुड़ सकें।

वंदे भारत स्लीपर का शुरुआती किराया 2300 रुपए

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2,300 तय किया गया है। सेकेंड एसी का किराया ₹3,000 होगा। फर्स्ट एसी का किराया करीब 3,600 प्रस्तावित किया गया है। स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिर तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। 30 दिसंबर को इस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कोटा-नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी। लोको पायलट ने 4 ग्लास में पानी रखा, इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास में से पानी नहीं छलका।

खास-खबर

विधायक मंडावी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

बीजापुर। विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपर तत्काल रोक लगाई जाए। विधायक ने बिना अनुमति के कटाई करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

कोरबा में नए खदान को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन

कोरबा। जिले में एक नए कोयला खदान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा लगभग चार प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों पर दबाव बनाकर जबरन प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। इसका मकसद रुंगटा कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक प्रक्रिया शुरू करना है। मरकाम ने कहा कि एक और खदान खुलने से बड़ी समस्या सामने आएगी।

रायपुर में एडवरटाइजिंग कारोबारी ने की आत्महत्या

रायपुर। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने अपने ही घर में जान दे दी। मृतक की पहचान रंजन पुरोहित के रूप में हुई है, जो विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि रंजन पुरोहित कुछ समय से आर्थिक परेशानियों और कारोबार में आ रहे घाटे के कारण मानसिक दबाव में थे। रंजन अपने परिवार के साथ न्यू राजेंद्र नगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट ने जेल भेजा

जांजगीर-चांपा। जिले में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित राम कुमार शर्मा, निवासी परसा पाली, द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के अनुसार, आरोपीगण ने पीड़ित के साथ कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। इस मामले में विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए।

सुवेंदु अधिकारी ने ममता को भेजा नोटिस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। ऐसा न करने पर वे ममता के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। दरअसल, ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी कोयला तस्करी मामले में शामिल हैं। कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु के जरिए शाह तक जाता है।

उपलब्धि : 2025 में उर्वरक उत्पादन 524 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े

नई दिल्ली। भारत ने कृषि क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में देश की कुल उर्वरक जरूरतों का करीब 73 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन के जरिए पूरा किया गया है। यह उपलब्धि उर्वरक आयात पर देश की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का कहना है कि वह किसानों को सशक्त बनाने और देश भर में उर्वरकों की विश्वसनीय और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में घरेलू उर्वरक उत्पादन में निरंतर और स्थिर वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित सभी श्रेणियों में दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन में यह निरंतर वृद्धि भारत के उर्वरक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

उत्पादन के आंकड़े

2021	433.29 लाख टन
2022	467.87 लाख टन
2023	507.93 लाख टन
2024	509.57 लाख टन
2025	524.62 लाख टन

सरकारी नीतियों का कैसे मिला फायदा?

सरकार ने इस सफलता का श्रेय अपनी सक्रिय नीतिगत पहलों को दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और आपूर्ति बाधाओं से बचने के लिए सरकार ने रणनीतिक विविधीकरण की नीति अपनाई है और प्रमुख कच्चे माल के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने साफकिया है कि 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप वह उर्वरक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर और किफायती इनपुट उपलब्ध कराना और टिकाऊ कृषि विकास सुनिश्चित करना है। यह उपलब्धि न केवल कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है बल्कि वैश्विक झटकों के खिलाफभारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

कई ट्रेनें रद्द, नागपुर, कोरबा के यात्री होंगे परेशान

■ 11 व 12 जनवरी को रेलवे ने 8 पैसेंजर ट्रेनों को किया रद्द

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जनवरी को 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण काम चलेगा। जिसके कारण 11 और 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को आधे रास्ते ही चलाई जाएगी।

इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस पहले से ही 9 से 14 जनवरी तक रद्द है। रद्द होने वाली ट्रेनों में रायपुर-बिलासपुर और कोरबा-रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18113/18114) 14 जनवरी तक रद्द रहेगी। इस दौरान यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया है।

ईओडब्ल्यू ने मांगा अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव का प्रोडक्शन वारंट

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा भी सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी लगाई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे जांच का दायरा और फैल सकता है।

दरअसल, यह घोटाला वर्ष 2019 से 2023 के बीच की शराब नीति से जुड़ा बताया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई कंपकंपी

■ अंबिकापुर सबसे ठंडा, कई जिलों में तापमान लुढ़का

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड के असर में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है और आने वाले एक-दो दिनों तक सर्दी का असर बना रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दुर्ग, बालोद, रायपुर सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी रायपुर में सुबह के समय धुंध छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, बेमेतरा और रायपुर जिलों के एक-दो क्षेत्रों में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

रायपुर का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं माना क्षेत्र में पारा पांच डिग्री तक गिर गया है, जिससे साफ़ है कि कम दूरी में ही ठंड का असर अलग-अलग रूप में नजर आ रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड और ज्यादा तेज हो गई है। बीते 24 घंटों में अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं दुर्ग में दिन का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

कलेक्टर दीपक सोनी को भारत सरकार में मिली डायरेक्टर की पोस्टिंग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी का सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें पोस्टिंग दे दी है। वे जल्द ही यहां से रिलीव होकर केंद्र में ज्वाईनिंग देंगे।

दीपक सोनी 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे इस समय बलौदाबाजार कलेक्टर हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले केंद्र में प्रतिनियुक्ति की इच्छा जताई थी। छत्तीसगढ़ सरकार के एनओसी मिलने के बाद भारत सरकार ने उन्हें वहां पदास्थपना दे दी है। दीपक को हेल्थ में डायरेक्टर बनाया गया है। 2011 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के वे डेपुटेशन पर जाने वाले दूसरे आईएएस अधिकारी हैं। उनसे पहले डॉ सर्वेश भूरे दो महीने पहले डेपुटेशन पर गए हैं।

जयपुर में रेस लगा रही ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक मौत

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात रेसिंग कर रहे एक ऑडी कार ने कहर मचा दिया। मानसरोवर के भीड़भाड़ वाले इलाके में 120 की रफ्तार से दौड़ रही ऑडी कार पहले बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, फिर सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल्स में घुस गई। इस दौरान वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कार करीब 16 लोगों को रौंदते हुए एक पेड़ से टकराकर रुकी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं, चार लोग गंभीर घायल हैं। ऑडी में ड्राइवर सहित 4 लोग बैठे थे। इनमें जयपुर पुलिस का सिपाही भी है। घटना के तुरंत बाद भीड़ ने एक कार सवार को पकड़ लिया था। जबकि, एक युवक को शनिवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

ईरान में कोहराम : 217 प्रदर्शनकारियों की मौत

■ सीएससी मुख्यालय दिल्ली की सख्त कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

तेहरान ए.। ईरान की राजधानी तेहरान में बीती रात हुए बवाल में 217 लोगों की जान चली गई। जो आंदोलन 29 दिसंबर को महज बढ़ती महंगाई और गिरती करेंसी के खिलाफ़शुरू हुआ था, वो अब सीधे वहां के धार्मिक और राजनैतिक रूप से बड़े हिंसक जंग में बदल चुका हैं सड़कों पर उतरे लाखों लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका हैं।

यहां की हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के करीब 20 जगहों के 110 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग पूरी तरह फैल चुकी है। तेहरान के एक डॉक्टर ने बताया कि 6 बड़े अस्पतालों में अभी तक 217 लाशे लाई जा चुकी है उसने भी ये जानकारी इस शर्त पर बताई की उसका नाम न बताया जाये डॉक्टर के हिसाब से ज्यादातर लोगों को गोली लगी है इस भारी बवाल में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि 14 सेना के जवान भी मारे गए हैं। पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। तेहरान के मेयर अलीरेज़ा ज़कानी ने सरकारी टीवी बताया की, पुरे शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह हील गया है। इस भारी बवाल से भीड़ ने 26 बैंकों को लूट लिया है, 25 मस्जिदों और 10 सरकारी इमारतों को आग में झोक दिया है। इसके अलावा दमकल की गाड़ियां, बसें और कई अपार्टमेंट भी इस भारी हिंसा के भेंट चढ़ गए हैं।

आईएएस अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव व रिटायर्ड आईएएस अमिताभ जैन को फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में अहम नियुक्तियां करते हुए शासन ने पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

अमिताभ जैन के अलावा राज्य सूचना आयोग में दो और सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल और सीनियर पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा को शामिल किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन और अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत निर्धारित किए जाएंगे। यह अधिसूचना राज्य सूचना का अधिकार (केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019 के अंतर्गत लागू होगी।

ताकझांक करनी हो तो बर्दाश्त बढ़ाइए

जांजगीर में एक विवाहिता ने इसलिए फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसके पति ने उसे थप्पड़ मार दिया था। विवाद के मूल में था एक मोबाइल फोन। घर में एक ही फोन होने के कारण पति-पत्नी दोनों उसका ही इस्तेमाल करते थे। बताया जाता है कि पति का विवाह के पहले से कोई अफेयर था। विवाह के बाद भी अफेयर जारी था। फोन में इस बात के सबूत थे कि वह अब भी उससे बात करती थी। यह भी उसे कॉल करता रहता था। तनातनी की मुख्य वजह यही थी। वैसे भी मोबाइल फोन से ज्यादा पर्सनल आज कुछ भी नहीं है। मोबाइल फोन पर किसी भी व्यक्ति के सारे राज मिल जाते हैं। वह नेट पर क्या देखता है, फोन पर किससे कितने मिनट बात करता है, किसे वीडियो कॉल करता है, सबकुछ मोबाइल फोन को पता होता है। थोड़ी सी जानकारी हो तो मोबाइल पर ट्रैकर डालकर पति या पत्नी एक दूसरे के सारे मूवमेंट्स को भी ट्रेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप को हैक कर उसके चैट को रियल टाइम में देखा जा सकता है। इसलिए मोबाइल कंपनियों ने सुरक्षा के तमाम सामान भी मुहैया कराए हैं। फिंगर प्रिंट, फेस स्कैनर, पासकोड जैसे हथियारों का एकल या समूहिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यहां बात मोबाइल को सुरक्षित रखने की नहीं हो रही। मोबाइल में ताकझांक करने की हो रही है। एक जमाना था पति अपनी पत्नी का हैण्डबैग भी नहीं छूते थे। पति-पत्नी एक दूसरे की प्रिवेसी का सम्मान करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब चोर पकड़ने का खेल चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है बशर्ते की आपकी बर्दाश्त अच्छी हो। वरना क्या फायदा कि आपने मोबाइल में ताकझांक की, उसे देखकर आपको सदमा लगा और आपने अपने ही जीवन को नरक बना लिया। प्रिवेसी में ताकझांक केवल उसे नहीं परेशान करती जिसकी गोपनीयता भंग हुई हो, बल्कि उसे ज्यादा परेशान करती है जिसने अहेतुक ताकझांक की होती है। इसलिए बेहतर है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे की प्रिवेसी का सम्मान करें। रिश्तों में लिहाज के आवरण को बने रहने दें।

जशपुर धान का अवैध परिवहन 30 क्विंटल धान जब्त

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की चौकी उपरकछार क्षेत्रांतर्गत जशपुर पुलिस के द्वारा फिर एक पिकअप वाहन से 60 बोरी में 30 क्विंटल धान को पकड़ा गया है। जिसकी कीमत लगभग 69,000 रुपए है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध पिकअप में भारी मात्रा में धान लोड है। सूचना पर गढ़वा केला के पास ग्रामीण रास्तों में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पिकअप वाहन दिखाइढ़ पुलिस को देख भगाने लगा और कुछ दूरी पर छोड़कर भाग गया। पुलिस के द्वारा पिकअप वाहन सहित उसमें लोड 60 बोरी में 30 क्विंटल धान को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सौंपा।

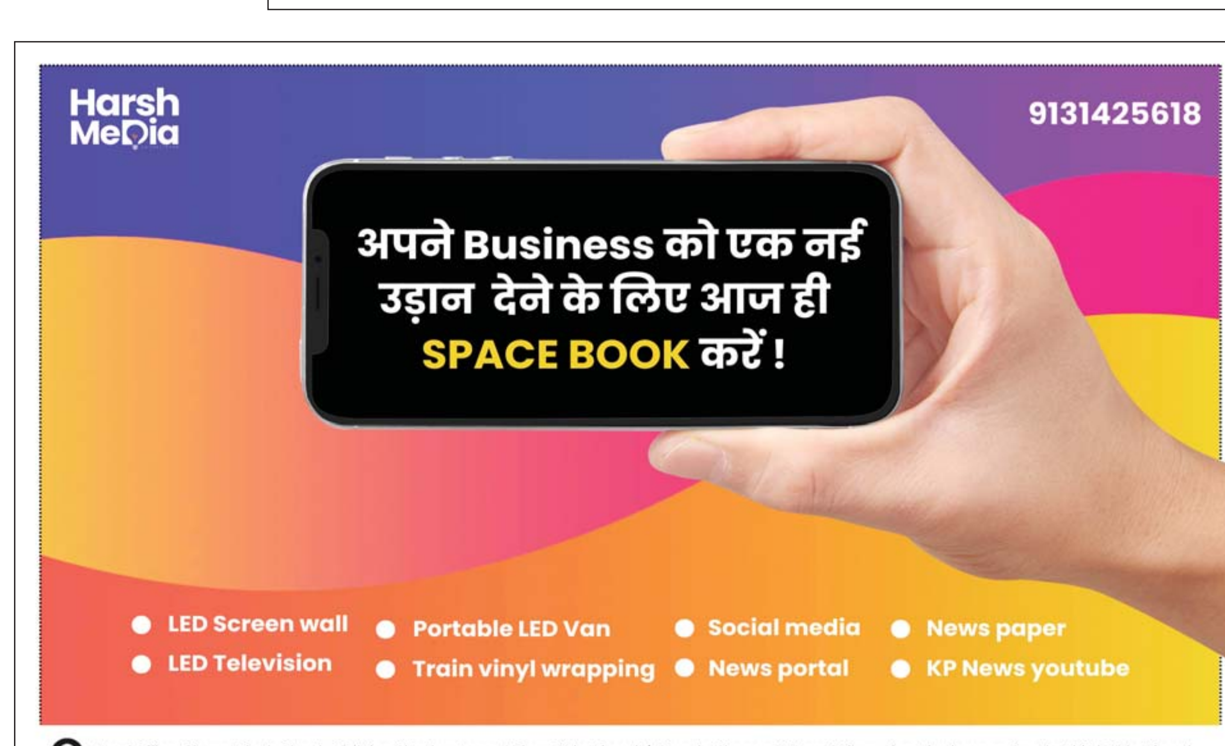

संपादकीय

दूषित पेयजल

इंदौर से सबक ले रोहतक को राहत दें

यह विडंबना ही है कि हमारे नागरिक प्रशासन का नियामक तंत्र आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से मुक्त नहीं होता। यदि समय रहते संवेदनशील या फिर घातक साबित होने वाली स्थिति व परिस्थिति पर नजर रखी जाए तो जनधन की हानि टाली भी जा सकती है। हाल ही में दूषित पेयजल से इंदौर में हुई जन हानि के बाद रोहतक और झज्जर की उन चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती,जिसमें नागरिक घरों में आने वाले गंदे व बदबूदार पानी की शिकायत करते रहे हैं। निश्चय ही इस स्थिति को जन स्वास्थ्य से जुड़े आपातकाल के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों की शिकायत की जांच-पड़ताल कर अविलंब कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही न निभाने और एक-दूसरे विभाग पर दोष मढ़ने का पुराना सिलसिला ही अकसर सामने आता है। उल्लेखनीय है कि इंदौर की हालिया दूषित पेयजल की त्रासदी में नगरपालिका द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के सेवन से कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विडंबना यह है कि वहां भी नागरिकों की शुरुआती चेतावनियों को सामान्य शिकायतों के रूप में देखकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इंदौर में पेयजल पाइपलाइनों में सीवेज का रिसाव हुआ था। यह स्वीकारोक्ति भी तब सामने आई जब बड़ा नुकसान हो चुका था। लगता है कि रोहतक व झज्जर भी इसी तरह के आसन्न खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आने वाले ऐसे मामले न तो रहस्यमय हैं और न ही ये कोई नई बात ही है। बुनियादी ढांचागत व्यवस्था का जर्जर होना, सीवर लाइनों में रिसाव, अनियोजित शहरी विस्तार और नागरिक एजेंसियों के बीच आवश्यक समन्वय का अभाव, अकसर ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, जहां सीवेज और पीने का पानी खतरनाक रूप से एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं।

> “ निर्विवाद रूप से दूषित जल से डायरिया, हेपेटाइटिस और अन्य दूषित जल जनित बीमारियों का प्रभाव तेजी से फैलता है। जिसके चलते अफरा-तफरी के बीच अक्सर स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में तंत्र की निष्क्रियता की कीमत आम लोगों को न केवल अस्पताल के भारी-भरकम बिलों के रूप में, बल्कि जानमाल के नुकसान और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में आई कमी के रूप में भी चुकानी पड़ती है।

गाहे-बगाहे देश के विभिन्न भागों में स्थानीय नागरिक जब-तब आरोप लगाते हैं कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिलने की आशंका है। ऐसे में शासन-प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया, इसके सत्यापन, पाइप लाइन की मरम्मत और वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य संकट को दूर करने और अपनी बात मनवाने के लिये यदि नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है तो यह शासन-प्रशासन की विफलता को ही दर्शाता है। विडंबना यह है कि जल प्रदूषण का सबसे बुरा असर समाज के कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इसकी चपेट में आते हैं। निर्विवाद रूप से दूषित जल से डायरिया, हेपेटाइटिस और अन्य दूषित जल जनित बीमारियों का प्रभाव तेजी से फैलता है। जिसके चलते अफरा-तफरी के बीच अक्सर स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में तंत्र की निष्क्रियता की कीमत आम लोगों को न केवल अस्पताल के भारी-भरकम बिलों के रूप में, बल्कि जानमाल के नुकसान और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में आई कमी के रूप में भी चुकानी पड़ती है। निश्चित रूप से दूषित पाइपलाइनों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में जल स्रोतों का परीक्षण होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लिए गए पानी के नमूनों की जांच के परिणाम भी सार्वजनिक किए जाएं।

इसके अलावा आवश्यक है कि दूषित सिस्टम के सुरक्षित प्रमाणित होने तक सुरक्षित वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी तय की जाए, न कि बांटी जानी चाहिए। सही मायनों में शहरी प्रशासन की कुशलता को स्वच्छ जल, स्वच्छता और जन-सुरक्षा जैसी बुनियादी बातों के मूल्यांकन के आधार पर मापा जाना चाहिए। ऐसे में इंदौर के घटनाक्रम को एक चेतावनी मानते हुए रोहतक और झज्जर के मामले में तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।

मिथ्या चेतना का दर्शनशास्त्र

हरदीप एस पुरी

भारत में 2026 के आरंभ में सार्वजनिक बहस नववर्ष के अनुशासन के साथ शुरू होनी चाहिए। हमें पड़ताल और तीखी आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि बहस के साथ जवाबदेही शामिल हो। कुल 1.4 अरब की आबादी वाले गणराज्य को निराशावाद से नहीं सुधारा जा सकता। रोजगार, उत्पादकता, निर्यात और समावेशन सबसे अच्छे समय में भी आसान नहीं होते। प्रगति डिजाइन, क्रियान्वयन, सुधार और परिमापन के नीरस मेल से आती है। नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का भी क्षण है।

फ्रेडरिक नीत्शे ने ‘बेयांड गुड एंड ईवल’ में लिखा है: ‘दार्शनिक को सिर्फ आलोचक या दर्शक होने के बजाय मूल्यों का सर्जक होना चाहिए। उसे तत्वचिंतन जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके नजरिए से करना चाहिए।’ लोकनीति में इसी तरह के दृष्टिकोण की दरकार है। आलोचनाओं का स्वागत है। मगर ये साक्ष्य तथा एक जटिल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र का शासन चलाने की ज्वलंत बाधाओं से आबद्ध होनी चाहिए। जब संशयवाद एक भंगिमा बन जाए तो यह सुधार संभव बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास को खत्म करता है।

पिछले वर्षों में टिप्पणी की एक नई विधा सामने आई है। यह संदेह को सुसंस्करण के तौर पर पेश करती है। यह सुधार के कार्य को मजाक में तब्दील कर देती है। यह हर अपूर्ण परिवर्तन को स्थाई नाकामी के सबूत के तौर पर लेती है। यह एक चिरपरिचित सांत्वना पेश करती है: भारत कदाचित अपने ही नीति निर्माताओं से अभिशप्त है। इस दृष्टिकोण के अपने नतीजे हैं। यह आंकड़ों और बाजारों में विश्वास को घटाता है। यह उद्यमियों और निवेशकों में नियतिवाद को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह बाहरी ताकतों को वार्ताओं में भारत को दबाव में लाने के लिए तैयार कथानक भी प्रदान करता है। विशेषज्ञता को तथ्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए।

मजबूत पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि का दंभ भरने वाले कुछ टिप्पणीकारों का इस तरह की भंगिमा का सहारा लेना चिंता की बात है। इनमें से कुछ ऐसे टिप्पणीकारों को मैं जानता हूं जिनकी पहचान और विश्वसनीयता भारत पर आधारित है। लेकिन वे संभवत: ध्यानाकर्षण या अब सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ अनाप-शनाप बोल कर अपना कॅरियर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

उनका यह आरोप कि भारत के आंकड़े विशिष्ट तौर पर अविश्वसनीय हैं, हमारी विकास की दिशा के साथ मेल नहीं खाते। माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत टैक्स संग्रह में जो वृद्धि हुई और इसने अनुपालन की जिस संस्कृति को पैदा किया है वह एक दशक पहले नहीं थी। वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। यानी औसतन प्रति माह 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रदर्शन का एक और निशान छोड़ा है। नवंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 20 अरब लेन-देन किए गए। ये वृहत और परखे जाने योग्य आंकड़े परिमापन, सत्यापन और तौरतरीकों में सुधार के लिए संभावना का विस्तार करते हैं।

कल्याण और समावेशन में परिमापित परिणाम इस नियतिवाद की और हवा निकाल देते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 24 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। अब बहुआयामी निर्धनता लगभग 30 प्रतिशत से घट कर तकरीबन 11 प्रतिशत रह गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से डिलीवरी दुरुस्त हुई है। वर्ष 2025 में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ। डीबीटी काल में धन के अपव्यय में कमी के जरिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की बचत हुई। वित्तीय समावेशन 56 करोड़ से ज्यादा जन धन खातों के साथ अब सार्वजनिक अवसंरचना बन गया है।

वित्तीय अनुशासन में सुधार के प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैरनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 2018 में 11.2 प्रतिशत से घट कर 2025 में 2.1 प्रतिशत रह गई है। यह सिर्फ खयाली पुलाव बनाने से नहीं हुआ। यह बैलेंस शीट्स की लगातार सफाई, सख्त निगरानी और एक ऐसे तंत्र को प्रतिबिंबित करता है जिसने सदाबहार ऋण और गुप्त हानियों की गुंजाइश को समय के साथ घटाया है। जब आलोचक कहते हैं कि शासन सुधार नहीं कर सकता तो यह आडंबरहीन कायाकल्प उनके लिए पहला जवाब है।

भारत बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं कर सकता यह आरोप लगाने वाले मैन्युफैक्चरिंग परिवेश में हुए बदलावों को नज़रअंदाज़ करते हैं। उत्पादन-से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के तहत, 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है जिससे 18 लाख करोड़ रूपए से ज़्यादा का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इसका सबसे सटीक उदाहरण है- साल 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन 11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया। इसमें अकेले मोबाइल फोन का उत्पादन 5.5 लाख करोड़ रुपये रहा और मोबाइल का निर्यात लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। ये दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्र के बाजार की परीक्षा है जिसमें भारत सफल रहा है।

व्यापार में आपकी पकड़ बेहतर प्रदर्शन और निरंतर टिके रहने से बनती है, न कि केवल निराशा जताने से। साल 2024-25 में सामान और सेवाओं का कुल निर्यात 825 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। टैरिफ और संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं की इस दुनिया में साझेदार आपकी क्षमता के आधार पर फैसला करते हैं। भारत की स्थिति तब और मजबूत होती है जब दुनिया उसे एक ऐसे बाजार के रूप में देखती है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और खरीदता भी है और अब देश ज़रूरी क्षेत्रों में भरोसेमंद तरीके से अलग-अलग तरह की आपूर्ति कर सकता है। घरेलू सुधार और बाहरी दुनिया से जुड़ाव मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं और यही मजबूती हमें व्यापार के क्षेत्र में और मजबूत बनाती है।

किसी भी देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति केवल एक योजना या एक मंत्रालय से नहीं आती, बल्कि यह बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सुधारों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होती है। भारत में यह सुधार औद्योगिक गलियारों, मालगाड़ियों की बेहतर कनेक्टिविटी, बंदरगाहों के बेहतर जुड़ाव और एक साथ काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिससे समय की बचत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अब व्यवस्था बनाने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बड़े पैमाने पर परिणाम देने की अपनी क्षमता को साबित किया है। सही तरीके से काम करने से उत्पादकता हफ्तों में नहीं बढ़ती बल्कि इसमें कई वर्ष लग जाते हैं।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कमियां गिनाना और यह मान लेना आसान है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब नीति का रुख बदल गया है। अब सरकार का ध्यान सीधे तौर पर मदद पहुँचाने और ऐसी संपदा बनाने पर है, जो उत्पादकता और सम्मान दोनों बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 12.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पानी का कनेक्शन पहुँचाया गया है। इससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि परिवारों पर पानी भरने के बोझ कम हुआ है और समय की बर्बादी भी कम हुई है।

विकास के लाभ सब तक पहुँचने की कहानी स्वास्थ्य, आवास और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। आयुष्मान भारत ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी किए हैं, जिससे परिवारों को गंभीर बीमारियों के भारी खर्च नहीं करने पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे परिवारों को न केवल अपनी संपत्ति मिली है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ठोस आधार भी दिया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे उन घरों तक स्वच्छ ईंधन पहुँचा है जो कभी धुएँ और कठिन परिश्रम के जाल में फंसे थे। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह वह व्यावहारिक आधार है जिस पर लोगों की आकांक्षाएँ और उनकी कार्यक्षमता टिकी है।

सबसे ज़्यादा निराशा अक्सर राज्यों की स्थिति को लेकर जताई जाती है जैसे कि एक अरब से ज़्यादा लोगों के देश को एक ही तरीके से चलाया जा सकता हो। भारत का संघीय ढांचा थोड़ा शोर-शराबे वाला ज़रूर है, लेकिन यह वक्त के साथ बदलना भी जानता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने यह दिखा दिया है कि बेहतर कानून-व्यवस्था, परियोजनाओं की शीघ्र मंज़ूरी और अवसंरचना के निर्माण में निरंतर काम से निवेश और बेहतर नौकरियाँ मिल सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को और मज़बूत किया है। इसके लिए ऐसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनसे राज्य जुड़ सकते हैं, ऐसा फंड बनाया है जो बेहतर काम करने पर इनाम के तौर पर दिया जाता है और सुधारों के आंकड़ों को इतना पारदर्शी बना दिया है कि जनता खुद सरकार के काम का फैसला कर सके।

भारत की प्रगति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इस पर हमेशा बहस होती रहेगी। सवाल यह है कि नए साल की शुरुआत में हम किस तरह की बहस चुनते हैं। जब बड़े-बड़े पेशेवर लोग केवल अनुमानों या इशारों को ही %गहन विश्लेषण% मान लेते हैं, तो वे उन संस्थाओं को कमज़ोर करते हैं जो सुधारों को मुमकिन बनाती हैं। यहाँ नीत्शे की बात याद करना ज़रूरी है - एक गंभीर विचारक ऐसे मूल्य पैदा करता है जो समाज को जीने और बेहतर बनने में मदद करें। भारत ने काम करके दिखाने का कठिन रास्ता चुना है। ये नतीजे ही हैं, जो आंकड़ों में भी दिखते हैं और महसूस भी किए जाते हैं।

यह किसी भी तरह की निराशा पर भारी पड़ेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। साल 2026 में, भारत को ऐसी आलोचना की मांग करनी चाहिए जो नीतियों को बेहतर बनाए, न कि ऐसी टिप्पणियों की जो केवल वाहवाही लूटने के लिए देश के आत्मविश्वास को कमज़ोर करती हों। यह वह मानक हैं जो देश के भीतर सुधारों, निवेश और लोकतांत्रिक विकल्प की रक्षा करते हैं।

(लेखक भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं)

सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान: स्वस्थ बचपन-सशक्त मातृत्व की दिशा में राज्य का संकल्प

डॉ. दानेश्वरी संभाकर
उप संचालक (जनसंपर्क)

छत्तीसगढ़ शासन के गठन के 25 वर्ष एवं वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान की प्रभावशाली शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रारंभ यह अभियान कुपोषण एवं एनीमिया जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। यह अभियान 1 जनवरी 2026 से प्रदेश के आठ संवेदनशील एवं चयनित जिलों—बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर—में एक साथ लागू किया गया है। अभियान का मूल उद्देश्य कुपोषण मुक्त

बचपन और स्वस्थ मातृत्व सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने तथा 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं, विशेषकर गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया की समस्या को प्रभावी रूप से कम करने पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसी भी राज्य का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य और माताओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण के विरुद्ध केवल योजनागत नहीं, बल्कि संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। यह अभियान सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत आगामी छह महीनों में महिलाओं में रक्ताल्पता की दर में उल्लेखनीय कमी लाने, गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में ठोस सुधार करने तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत कुपोषण से मुक्ति के उद्देश्य से समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुपोषण की दर में कमी लाने तथा एनीमिक गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएंगे। गंभीर एवं मध्यम कुपोषित (एसएएम, एमएएम) बच्चों, संकटग्रस्त बच्चों तथा चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से कवर किया जाएगा। अभियान के तहत सुपोषण दूतों का चयन किया जा रहा है, जो 70 प्रतिशत मध्यम कुपोषित एवं 30 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लेकर विभागीय योजनाओं एवं समुदाय के सहयोग से उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को सामान्य पोषण स्तर में लाने पर सुपोषण दूतों को प्रति बच्चा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार महिला स्व-सहायता समूहों को भी कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल से जोड़ा जाएगा, जिन्हें निर्धारित मानदेय के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुपोषण के प्रभावी प्रबंधन एवं सतत निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रबंध समिति का गठन किया गया है। साथ ही कुपोषित बच्चों को स्थानीय निधि से पोषण आहार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जनसहयोग और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाकर प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक माता तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। सतत निगरानी, पारदर्शी क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही के साथ यह अभियान कुपोषण एवं एनीमिया के विरुद्ध निर्णायक परिणाम देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

आखिरकार 2025 में श्रम अधिशेष का लाभ उठाने में सक्षम हो सका भारत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक, भारत सुरक्षित अर्थव्यवस्था के अनुरूप कड़े नियंत्रित श्रम ढाँचे के तहत काम करता रहा। यहाँ तक कि उदारीकरण के बाद भी यह ऐसा क्षेत्र था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि श्रम-अधिशेष वाले देश में भी कंपनियाँ श्रम-प्रधान निवेश से बचती रहीं। श्रम के व्यापक उपयोग में बाधा बन रहे श्रम कानून के इस असंतुलन को आखिरकार 2025 में सुधारा गया। अंतत- श्रम सुधारों और वीबी-जी राम जी के लागू होने से भारत के लिए अब यह संभव हो गया है कि वह शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अपने श्रम अधिशेष को औपचारिक अर्थव्यवस्था में समाहित कर सके। श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और उद्यम नीति पहली बार एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। इसकी बदौलत भारत एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो औपचारिक रोजगार तथा उद्यमों के विस्तार को सक्षम बनाते हुए श्रमिकों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

चलिए, उन देशों से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने भारत जैसी ही चुनौती —श्रम के अधिशेष का सामना किया। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया ने श्रमिकों को बड़े पैमाने के विनिर्माण में समाहित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूर्वानुमेय और अनुपालन को प्रबंधनीय बनाते हुए श्रम कानून बनाए।

भारत ने इसके उलट रास्ता अपनाया। उसने अनुमतियों और जुर्मानों की एक जटिल भूलभुलैया खड़ी कर दी, जिसने श्रम-प्रधान निवेश को हतोत्साहित किया और कंपनियों को अनौपचारिकता की ओर धकेल दिया।

शहरी और ग्रामीण, दोनों श्रम बाज़ारों में रुख अब बदल गया है। भारत ने 29 श्रम क़ानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करते हुए अपने समकक्ष देशों की तुलना में अनुपालन को कहीं अधिक सरल बना दिया है। उसने अपने श्रमिक संरक्षण के स्तर को समकक्ष देशों के बराबर रखा है, और भर्ती में लचीलेपन के मामले में वह उनसे आगे बढ़ गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा से विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की दिशा में बदलाव ने रोजगार को उत्पादकता से जोड़ दिया है। इसमें बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल है, ताकि खेतिहर श्रमिकों की कमी न हो और कार्य को टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी श्रम व्यवस्था बनी है, जो चीन, वियतनाम या इंडोनेशिया की तुलना में निवेश के लिए अधिक तैयार है, जिसमें कारखानों से लेकर खेतों तक पूरे श्रम तंत्र में अनुपालन में सुगमता, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बिना सुरक्षा मानकों को कमजोर किए बड़े पैमाने पर भर्ती की क्षमता मौजूद है।

श्रम सुधार- बिखराव से कार्यकुशलता की ओर

लगभग 100 श्रमिकों वाली एक छोटी विनिर्माण इकाई की कल्पना कीजिए। वर्षों तक, विकास के साथ चिंता भी जुड़ी रही। कुछ अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करने का मतलब था—श्रम कानूनों की जटिल भूलभुलैया से गुजरना, कई तरह के पंजीकरण कराना, मोटे-मोटे रजिस्टर बनाना, अलग-अलग प्राधिकरणों की निरीक्षण कार्रवाइयों का सामना करना, और इस बात का जोखिम उठाना कि कोई मामूली सी प्रक्रियागत चूक भी आपराधिक दायित्व को दावत दे सकती है। लिहाजा, कई व्यवसाय एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे- विस्तार करने की बजाय छोटा, अनौपचारिक और कम श्रमिकों के साथ बने रहना ही अधिक सुरक्षित है ।

यह मानसिकता 2025 में बदलनी शुरू हुई। 29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने से व्यवस्था नियामकीय अव्यवस्था से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ी। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाया गया है; अब निरीक्षण दोष खोजने के बजाय सहयोग और सुविधा प्रदान करने लगे हैं; और सामान्य, रोज़मर्रा की त्रुटियाँ अब आपराधिक दंड को आमंत्रित नहीं करतीं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरलीकरण श्रमिक के अधिकारों की कीमत पर नहीं हुआ है। मज़दूरी संरक्षण को सार्वभौमिक बनाया गया है, लैंगिक समानता को क़ानून में अंतर्निहित किया गया है, सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों तक बढ़ाया गया है, और प्रवासी श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी का लाभ मिला है। अब औपचारिक रूप से श्रमिकों को नियुक्त करना किसी जोखिम को संभालने जैसा नहीं, बल्कि भरोसे के साथ उठाया जाने वाला कदम बन गया है—जिससे विकास, सुरक्षा और विस्तार तीनों एक साथ संभव हो पाए हैं।

उद्यमों को बढ़ने और कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम बनाना

कई वर्षों तक, विकास करना ही अपने आप में एक प्रकार का दंड था। किसी विनिर्माण कंपनी की कल्पना कीजिए, जो बड़े पैमाने पर पहुँचने की कोशिश कर रही हो- जैसे ही उसकी चुकता पूँजी 4 करोड़ रुपये को पार करती थी, वह अपनी लघु कंपनी के दर्जे को खो देती और उसी समय अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के बीच अनिवार्य कैश-फ्लो स्टेटमेंट, अतिरिक्त बोर्ड और ऑडिट आवश्यकताएँ, और कंपनी रजिस्ट्रार के पास विस्तृत वार्षिक फाइलिंग —जैसे भारी अनुपालनों में उलझ जाती। इसका जवाब कई व्यवसायों ने आकार को सीमित रखकर, संचालन को विभाजित करके या अनौपचारिक बने रहकर दिया।

यह स्थिति 2025 में बदल गई। अब कंपनियाँ 10 करोड़ रुपये तक की चुकता पूँजी के साथ लघु कंपनी की श्रेणी में बनी रह सकती हैं, जबकि एमएसएमई निवेश सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा 2 गुना बढ़ा दी गई है। विकास अब अनुपालन संबंधी आघात का कारण नहीं बनता; बल्कि औपचारिकीकरण, विस्तार और नई भर्ती के लिए अवसरों का सृजन करता है, जो उद्यम आधारित रोजगार सृजन को नियामकीय जोखिम के स्थान पर समझदारी भरा विकल्प बनाता है।

वर्षों तक, श्रम कानून औपचारिक भर्ती को हतोत्साहित करते रहे, क्योंकि नियोक्ता पूर्ववर्ती दायित्व, पिछली तिथियों के बकाया भुगतान, और यहाँ तक कि कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से जुड़ी चूक के लिए भी दंडात्मक हर्जाने के जोखिम के कारण अक्सर कर्मचारियों को भविष्य निधि में नामांकित करने से बचते थे।

इस अनिश्चितता ने औपचारिक रोजगार को जोखिमपूर्ण बना दिया था, जबकि कड़े निकासी नियमों के कारण कर्मचारी संकट के समय अपनी बचत तक पहुँच नहीं पाते थे।

मोदी सरकार ट्रंप को उचित जवाब दे

ट्रंप ने जिस तरह मोदी की उनसे मिलने की कथित बेसब्री का जिक्र किया और अपाची हेलीकॉप्टरों के सौदे पर गलतबयानी की, वह सिरे से अस्वीकार्य होना चाहिए। मगर इस पर भी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया!

डॉनल्ड ट्रंप अपनी खामख्यालियों में रहते हैं। आत्म-प्रशंसा में बहते हुए वे अपनी खूबियों का बखान तो करते ही हैं, दूसरों का अपमान करने की हद तक भी अक्सर जाते रहते हैं। इस दौरान वे सच-झूठ की फिक्र नहीं करते। बतौर के अपने दूसरे कार्यकाल में अपमान के तीर उन्होंने जिन निशानों पर बार-बार छोड़े हैं, उनमें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। दरअसल, भारत के मामले में बात सिर्फ जुबानी तीर की नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा आयात शुल्क भारतीय वस्तुओं पर लगा कर अमेरिको को निर्यात से जुड़े देश के कारोबार को भारी क्षति पहुंचाई है। इसी तरह एच-1बी वीजा और स्टूटेंड वीजा के मामलों में उनके प्रशासन ने भारत के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाए रखा है।

हैरतअंगेज ही है कि अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अति संवेदनशील रहने वाली मोदी सरकार ने ट्रंप के हमलों पर चुप्पी साधे रखी है। मगर अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। अपने ताजा बयान में जिस तरह उन्होंने मोदी की उनसे मिलने की कथित बेसब्री का जिक्र किया और अपाची हेलीकॉप्टरों के सौदे को लेकर गलतबयानी की, वह सिरे से अस्वीकार्य होना चाहिए। बिना तथ्यों की जांच किए उन्होंने 68 हेलीकॉप्टरों का जिक्र किया, जबकि भारत ने 28 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा ही किया है और उनकी जल्द डिलीवरी कराने में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। मगर इस पर भी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया!

इस चुप्पी के पीछे अगर गणना यह है कि इससे ट्रंप खुश होंगे और भारत से अनुकूल व्यापार समझौता कर लेंगे, तो ऐसी कोई उम्मीद निकट भविष्य में पूरी होती नहीं दिखती। इसलिए अब चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की ट्रंप से कितनी गहरी व्यक्तिगत दोस्ती है, यह देशवासियों को नहीं मालूम। यह जानने में उनकी दिलचस्पी भी न्यूनतम है। मगर मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वे भारत की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

युवा दिवस पर भाषण, रंगोली तथा काव्य पाठ प्रतियोगिता

दुर्ग। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भाषण, रंगोली तथा काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजन नगर पंचायत उतई, मंगल भवन, वार्ड क्र. 7, जिला-दुर्ग में प्रात: 11 बजे से किया जा रहा है। जिले के समस्त स्कूल/ कॉलेज के विद्यार्थी एवं खिलाड़ी भाग ले सकते है। आयोजन में भाग लेने के लिए आयु वर्ग 15 से 29 वर्ष है। रंगोली प्रतियोगिता का विषय युवा शक्ति एवं स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित होगा। काव्य पाठ प्रतियोगिता का विषय उठो जागो स्वामी विवेकानंद जी का अमर संदेश पर आधारित होगा। अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी अशोक रिगरी मोबाईल नंबर 9229575220, 8770527628 एवं प्रशिक्षक भूपेन्द्र हिरवानी मोबाईल नंबर 9584078910 से संपर्क कर सकते है।

दक्ष वैद्य बने किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह प्रभारी

भिलाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की अनुशंसा पर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर एवं प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी डॉ. नवीन मारकण्डे ने युवा कृषक दक्ष वैद्य साहू को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाने और आधुनिक कृषि क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खेलो इंडिया के तहत कबड्डी में पाटन से 4 का चयन

दुर्ग। वर्ष 2025-26 के लिए 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर (पुरुष/ महिला) कबड्डी चौंपियनशिप का आयोजन 09 से 11 जनवरी 2026 तक कोरबा जिले के लाल मैदान दर्री में किया जा रहा है। जिसमें खेलो इंडिया कबड्डी सेंटर मर्रा, पाटन से 4 खिलाड़ी बालिकाओं का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की टीम में बालिका आरती ठाकुर, जिगिशा यादव, ऐश्वर्या एवं काजल चंद्रवंशी के चयन पर खेलो इंडिया मिनी सेंटर मर्रा के कोच भरत लाल ताम्रकार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खेल अधिकारी प्रवेश जोशी, प्राचार्य सेजस मर्रा, खेल अधिकारी संतोष यादव ने बधाई दी है।

12वीं राज्य स्तरीय यूसीमास अबेकस प्रतियोगिता में दुर्ग के बच्चों ने लहराया परचम

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। यूसीमास द्वारा आयोजित 12वीं राज्य स्तरीय अबेकस एवं मेंटल अरिथमेटिक प्रतियोगिता का आयोजन 4 जनवरी को राम मंदिर स्थित महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप, वीआईपी रोड, रायपुर में किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से 5 से 13 वर्ष के 900 से अधिक बच्चों ने भाग लिया।

लिसनिंग प्रतियोगिता के बी 2 केटेगरी में वागास्कर आरोही अप्पा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में यूसीमास सिंधिया नगर, दुर्ग सेंटर के 93 विद्यार्थियों ने सहभागिता की और शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक पुरस्कार अपने नाम किए। हायर ए की केटेगरी एफ-2 में जिनय पटेल ने चैंपियन का खिताब जीता। इंटरमीडिएट बी की केटेगरी ई-1 में भव्या ठाकरे चैंपियन बने, जबकि

राघवन मंडावी ने पांचवा स्थान प्राप्त किया। इसी ग्रुप की केटेगरी ई-2 में एस. वी. आदित्य ने तीसराऔर अंशुमन कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट ए की केटेगरी डी-3 में आरोही अप्पा ने दूसरा तथा पूर्वी देवांगन ने छटवां स्थान प्राप्त किया। एलीमेंट्री ए की केटेगरी बी 1 में आदित्य कुमार छटवे स्थान पर रहे। बेसिक केटेगरी ग्रुप ए-1 में चारु देवांगन ने चौथा, ए-2 केटेगरी में चांदनी साहू पांचवा एवं ए-3 केटेगरी में श्रुति कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया 7 फाउंडेशन श्रेणी में शिवांश अप्आपा चैंपियन बने, वहीं अभिराज यादव ने पांचवां एवं आद्विक बंसल ने छटवां स्थान प्राप्त किया। जेड केटेगरी में एस. वी. सायशा ने पांचवां स्थान प्राप्त किया। भूमिका ठाकुर, भार्गवी बिसेन, आफिफा खानम, मोर्या कुमार साहू, हर्षित साहू, आध्या बोरेकर तथा अथर्व ठाकरे ने मेरिट रैंक प्राप्त किया।

सवा लाख मीट्रिक टन धान का उठाव, 79 लाख रुपए का हुआ भुगतान, किसान खुश

68163 किसानों को मिला धान का वाजिब दाम, 927 हेक्टेयर रकबा समर्पण

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले में अब तक 88,151.30 लाख रूपए की लागत से 3,71,857.80 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 68163 किसान लाभान्वित हुए हैं। उपार्जन केन्द्रों से धान की उठाव भी तेजी से होने लगी है। जिससे अब दूसरे किसानों को धान बेचने का अवसर मिला है। उठाव हेतु 1,94,036.72 मे. टन धान का डीओ जारी हुआ है।

अब तक उपार्जन केन्द्रों से 1,27,223.58 मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में किसान भी सहभागी बनते हुए धान बेचने के पश्चात् रकबा समर्पण करने आगे आ रहे हैं। जिससे बिचौलियों को अपनी धान खपाने का अवसर नहीं मिला है। जिले में अब तक धान बेच चुके 37983 कृषकों ने 926.87 हेक्टेयर रकबा

समर्पण कर चुके हैं। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने के लिए पहुंचने वाले किसानों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किया गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके तहत केन्द्रों में 28,38,803 बारदाने उपलब्ध है।

राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी और उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी आई है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। जिसके तहत अब दिन-रात कभी भी मोबाईल एप तुंहर टोकन के माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन मिलने लगा है। धान बेचने के बाद त्वरित भुगतान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की व्यवस्था से प्रभावित होकर किसान अपनी उपज बेचने टोकन प्राप्त किसान निर्धारित तिथि अनुसार उपार्जन केन्द्र पहुंच रहे हैं।

धान उपार्जन से मिली राशि बनेगी घर मरम्मत का सहारा

ग्राम अछोटी निवासी किसान नुलम साहू ने इस साल 2 एकड़ 30 डिसमिल खेत में धान बोया था। 40 क्विंटल धान का विक्रय किया है। नुलम अपनी पत्नी के साथ कुथरेल उपार्जन केंद्र पहुंचे थे। पत्नी शेड के नीचे बैठकर धान के कट्टों को निहारती नजर आईं। केंद्र पर सुविधाओं को देखकर किसान और उनकी पत्नी प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यहां किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। शेड, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि धान की उपज अपेक्षाकृत कम है। पर उपार्जन व्यवस्था से राहत मिली है। अब वे अपने घर की मरम्मत करवा पाएंगे।

निगरानी को सख्त करने एसएसपी दुर्ग ने कोर्ट मोहर्रिर व आरक्षकों को दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

- जमानत निरस्तीकरण को गंभीरता से लें
- रजिस्टर संधारण को लेकर दिये विशेष निर्देश
- कानूनी प्रक्रियाओं की भी दी खास जानकारी

दुर्ग। जिला दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस कण्ट्रोल रूम, सेक्टर-6 में रात्रि 8 बजे जिले के समस्त थाना एवं चौकी में कार्यरत कोर्ट मोहर्रिर एवं कोर्ट आरक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान एसएसपी ने चिन्हित अपराध योजना के तहत चयनित मामलों में दर्ज प्रथम सूचना पत्र (एफआईआर) से लेकर अंतिम न्यायिक विचारण तक की पूरी जानकारी अद्यतन रखने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अपराधों के विधिवत रजिस्टर संधारण पर विशेष जोर दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों एवं निगरानी बदमाशों के मामलों में जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाने के निर्देश देते हुए कोर्ट मोहर्रिर एवं आरक्षकों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत समझाइश दी।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मणि शंकर चंद्रा सहित जिले के सभी थाना एवं चौकी के कोर्ट मोहर्रिर/आरक्षक उपस्थित रहे। एसएसपी ने सभी कर्मचारियों से न्यायालयीन कार्यों में सतर्कता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखने की अपेक्षा जताई।

भिलाई निगम आयुक्त ने भ्रमण के दौरान सुनी नागरिकों की समस्याएं

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-5 अंतर्गत फुटबाल ग्राउण्ड, सफाई व्यवस्था, उद्यान, पानी टंकी सहित नाला का सघन निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया। नागरिकों से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत हुए।

निगम आयुक्त एवं जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे द्वारा सेक्टर 9 अस्पताल के बगल में बने फुटबाल ग्राउण्ड का निरीक्षण किये। फुटबाल ग्राउण्ड में लाईट, पानी एवं सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए बंद लाईट को शीघ्र चालू कराने निर्देशित किये हैं। हास्पिटल सेक्टर स्थित मार्केट एवं बस्ती का भ्रमण करते हुए सफाई, पानी, नाली, सुलभ का जायजा लिये।

बस्ती में निवासरत नागरिकों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवास लेने हेतु चर्चा किए हैं। आयुक्त ने सड़क 9-10 के बीच बने उद्यान का अवलोकन करते हुए वहां रोपित पौधो, खेल सामग्री एवं साफ-सफाई व्यवस्था को देखे, जो ठीक पाया गया। समीपस्थ पानी टंकी का निरीक्षण किये और पेयजल सप्लाई में किसी प्रकार की समस्या न हो इसका ध्यान रखने कहा गया है। आयुक्त द्वारा नाला का अवलोकन किया गया, स्थानीय निवासियों द्वारा पानी टंकी समीप पेवर ब्लाक लगाने मांग किया गया है।

जोन-1 और 3 में नाला चैनलाइजेशन, सार्वजनिक मंच प्रगति पर

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई शहर के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत नाला चैनेलाइजेशन, सार्वजनिक मंच, नाली निर्माण सहित रिटर्निंग वाल एवं पुलिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा नागरिकों की मांग एवं सुविधाओं को देखते हुए वार्ड क्रं. 3 माडल टाउन में नाला चैनेलाइजेशन एवं सार्वजनिक मंच निर्माण, वार्ड क्रं. 2 स्मृति नगर आंदन नगर में नाली निर्माण, कोसानाला में रिटर्निंग वाल एवं पुलिया निर्माण, सुपेला घड़ी चौंक से लोहिया पेट्रोल पम्प मुख्य मार्ग किनारे नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। मंच के निर्माण से नागरिकों को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराने में सुविधा मिलेगी। नाली एवं पुलिया के निर्माण हो जाने से सड़कों पर बेवजह बहने वाले पानी नाली के माध्यम से आसानी से आगे निकल जायेगा। भिलाई निगम शहर के विकास में लगातार कार्य कर रहा है।

ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता, कोलकाता

हेमचंद यादव विवि टीम ने बॉस्केटबॉल में जीता खिताब

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग/कोलकाता। युनिवर्सिटी ऑफ कोलकात्ता में दिनांक 08-09 जनवरी 2026 तक आयोजित ईस्ट जोन इंटर युनिवर्सिटी प्रतियोगिता में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की बॉस्केटबॉल पुरूष टीम लगातार सभी मैचों में जीत हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त की। टीम की इस जीत पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय तिवारी, कुलसचिव भूपेन्द्र कुलदीप व खेल संचालक डॉ. दिनेश नामदेव ने टीम की प्रसंशा करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी।

खेल संचालक डॉ. दिनेश नामदेव ने बताया कि बॉस्केटबॉल टीम प्रथम से अंतिम मैच तक जीत

का सिलसिला जारी रखा और प्रतियोगिता में सभी मैचों में जीत हासिल की। बास्केटबॉल टीम पहला सरला बिरला विश्वविद्यालय रॉंची को 88-21 पराजित की दूसरी मैच सेन्चुरियन विश्वविद्यालय को 59-20 से पराजित की, तीसरी मैच बुर्धवन विश्वविद्यालय को 73-45 से एवं चतुर्थ मैच में कॉशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को 74-45 से पराजित कर आल इंडिया के लिए क्वालीफाई की और जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सेमीफाईनल मैच में भी कलिंगा विश्वविद्यालय ओडिसा को 40-64 से, सम्बलपुर विश्वविद्यालय ओडिसा को 54-73 की बड़ी अंतर से पराजित कर फाइनल मैच में पहुँचे व फाइनल मैच युनिवर्सिटी आफ कोलकात्ता से मुकाबला रहा जिसमें 46-66 से जीत हासिल कर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की। टीम के सभी सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार राशि के हकदार हो गये जिन्हे विश्वविद्यालय द्वारा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी, मैनेजर व कोच को 10-10 हजार रूपये प्रदान किया जायेगा। यह टीम युनिवर्सिटी आफ मुम्बई में 21-24 फरवरी 2026 को आयोजित आल इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेगी। महाविद्यालय के क्रीड़ाधिकारीगण डॉ. ऋतु दुबे, डॉ. नरेश दीवान, डॉ. रमेश कुमार त्रिपाठी, डॉ. मून्नालाल नंदेश्वर, अरूण चौधरी एवं लक्ष्मेन्द्र कुलदीप ने बधाई दी व आगे के लिए शुभकामनाएं दी।

सिंगल यूज प्लास्टिक रखने वाले दुकानदारों पर की गई कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से व्यापारियों एवं नागरिको को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रतिष्ठान एवं फल ठेला वाले प्लास्टिक में सामग्री डालकर विक्रय कर रहे है।

प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और नष्ट नहीं होता है, फिर भी इसका उपयोग लगातार किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन-1 नेहरू नगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए समझाइस दिया जा रहा है।

शुक्रवार को वार्ड क्रं. 17 नेहरू भवन एवं वार्ड क्रं. 10 लक्ष्मी नगर के पास प्रतिष्ठानों एवं फल ठेला में पहुंचकर जांच किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक पाये जाने पर कार्यवाही की गई एवं प्लास्टिक को जप्त किया गया।

इन दुकानों पर लगाया गया जुर्माना

इन दुकानों पर किया गया कार्यवाही खंडेलवाल किराना दुकान 1000, संकल्प ट्रेडर्स 200, साहू दोना पत्तल दुकान 100, जीतू जसवाल फल ठेला 100, अनीता सोनकर फल ठेला 100, राधे श्याम फल ठेला 50, सारधा फल ठेला 50 इस प्रकर कुल 1600 रूपये की चालानी कार्यवाही किया गया है। यह भी समझाया गया है कि दुबारा जांच के दौरान प्लास्टिक पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति लाईसेंस निरस्त किया जाएगा।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ ग्रहण 15 जनवरी को

उत्तर बस्तर कांकेर। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक 100 दिनों का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सभी विद्यालयों, कॉलेजों, स्वास्थ्य केन्द्रों, छात्रावासों, पुलिस थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा न्यायालयों में 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा 18 जनवरी को

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह महत्वपूर्ण परीक्षा आगामी रविवार 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। जगदलपुर शहर में परीक्षा के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 1045 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पालना सहायिका एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 27 तक आवेदन

राजनांदगांव। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव (शहरी) अंतर्गत आरके नगर वार्ड नंबर 45 एवं मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री रविदास वार्ड नंबर 20 में पालना सहायिका के 1-1 पद तथा शिवनाथ वार्ड नंबर 51 में आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के लिए 27 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पालना सहायिका पद के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक निर्धारित तिथि तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव (शहरी) जिला राजनांदगांव में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना हेतु पंजीयन 30 जनवरी तक

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थी 30 जनवरी 2026 तक पंजीयन व सत्यापन करा सकते हैं। कक्षा 10वीं के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचिज जाति वर्ग एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी 12 जनवरी 2026 के पूर्व दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा और 15 जनवरी 2026 के पूर्व आपत्तियों का जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसके पश्चात 20 जनवरी 2026 को अंतिम मेरिट सूची जारी कर प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाएगी।

सीआरसी में 20 जनवरी तक बांस शिल्प कला प्रशिक्षण शिविर

राजनांदगांव। दिव्यांगजन कौशल विकास, पुर्नवास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) ठाकुरटोल राजनांदगांव में व्यावसायिक विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करने एवं उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के विकास के लिए 8 से 20 जनवरी 2026 तक बांस शिल्प कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बांस से बनाए जाने वाले विभिन्न आकर्षक उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में दिव्यांग बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हो रहे है। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में बांस शिल्प कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

खरीफ की फसल पर लगा टसर का तड़का, अतिरिक्त आय से केवट के जीवन में आई खुशहाली

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कोरबा जिले के ग्राम सलोरा निवासी 57 वर्षीय किसान भरत राम केवट ने टसर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत की है। सीमित संसाधनों और कृषि प्रधान परिवार में जन्मे श्री केवट ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिश्रम, लगन और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। टसर पालन उनके परिवार की आजीविका का सशक्त आधार बन चुका है।

श्री केवट के पास एक एकड़ भूमि है, जिसमें वे खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं। 1980 के दशक में श्री केवट ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के रामपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र से टसर पालन का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके पश्चात वे लगातार जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़ते रहे। उन्होंने टसर पालन की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वच्छता, चूना-ब्लीचिंग, नियमित निगरानी एवं रोगग्रस्त लार्वा के सुरक्षित निपटान जैसी वैज्ञानिक विधियों को अपनाया।

लगभग 33 वर्षों के अनुभव के आधार पर श्री केवट ने उच्च गुणवत्ता वाले टसर कोकून उत्पादन में विशिष्ट पहचान बनाई है। बीएसएमटीसी बिलासपुर से प्राप्त 145 डीएफएल के माध्यम से उन्होंने 10,000 बीज कोकून एवं 600 गैर-बीज कोकून का उत्कृष्ट उत्पादन किया, जो सामान्य उत्पादन दर से कहीं अधिक है। भविष्य में वे 500 डीएफएल पालन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

टसर पालन से उन्हें वर्ष में दो फसलें प्राप्त होती हैं, जिससे लगभग ढाई लाख रुपये की वार्षिक आमदनी होती है। इसी आय से उन्होंने दो तालाब बनाकर अनुबंध आधारित मछली पालन भी प्रारंभ किया है। टसर पालन ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। श्री केवट ने 8 से 10 किसानों को टसर पालन के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित भी किया। उनके मार्गदर्शन में कई किसान आज सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मान भी मिला है। श्री भरत राम केवट का कहना है कि टसर पालन ने मेरी जिंदगी बदल दी है।

'दीदी के गोठ' में दीदियों ने सुनाई सफलता की कहानियां, जोश और उमंग का नया साल

■ वित्तीय समावेशन पर 'दीदी के गोठ' के छठवें एपिसोड का हुआ प्रसारण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा संचालित लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'दीदी के गोठ' का छठवां एपिसोड गुरुवार को प्रसारित किया गया। इस एपिसोड में वित्तीय समावेशन पर स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रेरक कहानियों को बताया।

नव वर्ष के पहले एपिसोड में स्वसहायता समूह की दीदियों को प्रोत्साहित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नए साल में सभी स्वसहायता समूह की दीदियाँ नई उमंग से नई तरंग के साथ अच्छे से कार्य करें एवं संगठन को और भी मजबूत बनाएं। स्व सहायता समूह की दीदियां मिलकर संगठन और समूहों को सशक्त बनाएं। इस प्रकार हम सभी मिल कर तरक्की की राह तय करेंगे।

इस विशेष एपिसोड में दुर्ग, बालोद एवं गरियाबंद जिलों की दीदियों अपने जीवन के अनुभव साझा किया। जिसमें वित्तीय समावेशन से महिला सशक्तिकरण की मिशाल बनी बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखण्ड के ग्राम गब्दी की जय संतोषी स्व-सहायता समूह की श्रीमती खिलेश्वरी देवांगन ने बताया कि कैसे बिहान से जुड़कर वे सफ्लता और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहीं हैं।

गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत मैनपुर के ग्राम धुरवागुड़ी की बी.सी. सखी दीदी श्रीमती खेमेश्वरी तिवारी ने बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना काल के समय लोगों को घर पहुंच सेवा देते हुए आवश्यकता के समय मे घर घर तक लोगों को उनके पैसे दिलाये और लोगों की सेवा के साथ उन्होंने भी सफ्लता की सीढ़ियां चढ़ीं। कैसे वे अब भी घर सम्हालने के साथ-साथ बी.सी. सखी के रूप में समाज बदलने की जिम्मेदारी भी निभा रहीं हैं।

एफएलसीआरपी द्वारा वित्तीय साक्षरता, लेन-देन बैंक, बीमा इत्यादि के सम्बन्ध में जागरूक होकर गांव गांव में महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने वाली दुर्ग के जनपद पंचायत धमधा के ग्राम चीचा की जय सतनाम स्व-सहायता समूह की बीमा सखी श्रीमती कल्पना चतुर्वेदी ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि बिहान केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की यात्रा है। वित्तीय समावेशन केवल बिहान के अंतर्गत महिलाओं को आजीविका दिलाने का कार्य नहीं करता, बल्कि उसे स्थायित्व, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा देता है।

इस एपिसोड में महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जुड़कर नियमित बचत, ऋण, बीमा तथा डिजिटल लेन-देन जैसी वित्तीय सेवाओं से सकारात्मक और स्थायी बदलाव एवं ग्रामीण महिलाओं से राज्य की सशक्त होती अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। यह छठवां एपिसोड पूर्व की भांति हिंदी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी एवं सदरी में प्रसारित किया गया। पूरे प्रदेश की स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं एवं लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने घरों और केंद्रों में सुना और प्रेरणा प्राप्त की।

पुना मारगेम : 63 हाथों ने छोड़ी बंदूकें, मुख्यधारा में होंगे शामिल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर अंचल में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। दंतेवाड़ा जिले में 'पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन' पहल के अंतर्गत 36 इनामी सहित कुल 63 माओवादियों— जिनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं — ने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य के लिए एक निर्णायक परिवर्तन है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की स्पष्ट, बहुआयामी सुरक्षा एवं विकास रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रमाण है कि बंदूक नहीं, संवाद और विकास ही स्थायी समाधान हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति, सटीक सुरक्षा रणनीति और सुशासन आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। माओवादी नेटवर्क का प्रभावी विघटन हो रहा है और बस्तर के सुदूर अंचलों में अब तेज़ी से सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा सम्मानजनक पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर नागरिक बनकर समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से स्थापित हो सकें।

गुणवत्ताविहीन और अमानक कार्यों पर लोक निर्माण विभाग की कड़ी कार्रवाई जारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के गुणवत्ताहीन एवं अमानक कार्यों के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने आज कांकेर के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य पाए जाने पर दो अभियंताओं को निलंबित करने के साथ ही कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

लोक निर्माण विभाग के बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा कांकेर जिले के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार संपूर्ण डामरीकरण का कार्य अमानक स्तर एवं लंबाई 6.80 किमी में पुनः डामरीकरण कार्य संपादित कराये जाने में लोक निर्माण विभाग के चारामा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर और उप अभियंता एम.के. खरे ने पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया। साथ ही लगभग 70 प्रतिशत एम.एस.एस. पूरा उखड़ जाने, डामरीकरण मे बी.एम. की मोटाई भी एक समान नहीं पाये जाने, कोर लेने पर सैंपल टुकड़े-टुकड़े होकर निकलना तथा डामर बिछाते वक्त प्रॉपर कम्पैक्शन नहीं होना पाया गया।

डामरीकरण में बिटुमिन कंटेन का भी ध्यान नहीं रखा गया। सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन एवं अमानक स्तर का कार्य कराये जाने पर विभाग ने दोनों अभियंताओं को निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया है। दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

लोक निर्माण विभाग के कांकेर संभाग के कार्यपालन अभियंता केके सरल को इस गुणवत्ताहीन एवं अमानक कार्य पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन एवं अमानक स्तर के कार्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों की समयावधि में विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है। निर्धारित समयावधि में लिखित प्रतिवाद प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

श्रम कल्याण मंडल : 6 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं का लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आज 6000 से अधिक श्रमिक परिवारों को छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहायता योजना, खेलकूद प्रोत्साहन योजना ढाई करोड़ रूपए से अधिक की राशि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वितरित की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि श्रम कल्याण मंडल व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहने का कार्य उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ और खूब आगे बढ़ा, अब तक इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों मजदूरों को मिल चुका है।

उन्होंने मंडल द्वारा संचालित किफायती दर में भोजन उपलब्ध कराने की योजना का प्रशंसा करते हुए कहा कि कल्याण मंडल जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाकर मजदूर क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की श्रमिक कल्याण के हितों के लिए प्रदेश भर में चलाई जा रही 14 कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मजदूरों को हर परिस्थिति में मदद करने के लिए तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम कल्याण मंडल, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ढाई करोड़ से ऊपर की धनराशि का छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहायता योजना व खेलकूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूरों को प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में मंडल के कल्याण आयुक्त अजितेश पांडे, पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी, रामकृष्ण धीवर, रवि शंकर सिंह, राधेश्याम गुप्ता, कमल बॉस व विभिन्न उद्योगों से आए मजदूर उपस्थित थे।

अधोसंरचना विस्तार : 362 फीसदी बढ़ गए बिजली के उपभोक्ता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र में शामिल कोरिया जिले में बीते 25 वर्षों के दौरान विद्युत पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना का उल्लेखनीय और सतत विकास हुआ है। निरंतर, सुरक्षित एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के परिणामस्वरूप जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2000 में, जब वर्तमान मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला भी कोरिया जिले में शामिल था तथा जिले का क्षेत्रफल 6,228 वर्ग किलोमीटर था, उस समय कुल विद्युत उपभोक्ता (एलटी एवं एचटी) 25,922 थे। सितंबर 2022 में नए जिले के गठन के बाद कोरिया जिले का क्षेत्रफल घटकर 2,002 वर्ग किलोमीटर रह गया, इसके बावजूद विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 94,065 हो गई है। उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि लगभग 362 प्रतिशत है। इसी अवधि में निम्नदाब उपभोक्ता 11,617 से बढ़कर 48,965 हो गए हैं। बीपीएल कनेक्शन 4,354 से बढ़कर 21,026, घरेलू कनेक्शन 9,776 से बढ़कर 21,425 तथा सिंचाई पंप कनेक्शन 157 से बढ़कर 2,634 हो गए हैं।

बढ़ती मांग के अनुरूप अधोसंरचना का व्यापक विस्तार किया गया है। 132/33 केवी उपकेंद्रों की संख्या शून्य से बढ़कर 1, 33/11 केवी उपकेंद्र 2 से बढ़कर 10 तथा पावर ट्रांसफार्मर 3 से बढ़कर 15 हो गए हैं।

वितरण ट्रांसफार्मर 338 से बढ़कर 1,988, उच्चदाब लाइनें 897 किलोमीटर से बढ़कर 2,072 किलोमीटर तथा निम्नदाब लाइनें 449 किलोमीटर से बढ़कर 2,636 किलोमीटर हो गई हैं। निर्बाध आपूर्ति के लिए 5 वितरण केंद्रों से 45,675 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। इन प्रयासों से कोरिया जिले में शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

अल्पकालीन कृषि ऋणों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि धान खरीदी मॉड्यूल में हो : अपेक्स बैंक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदार नाथ गुप्ता की अध्यक्षता में आज नया रायपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 2058 पैक्स समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।

खरीफ एवं रबी फसलों के लिए निर्धारित 9 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7 हजार 261 करोड़ रुपये के ऋण वितरण किये जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 80.68 प्रतिशत है।

श्री गुप्ता ने निर्देश दिया कि वितरित कृषि ऋणों की चालू एवं कालातीत राशियों की प्रविष्टि पंजीयक मॉड्यूल तथा धान उपार्जन मॉड्यूल में तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि लिंकिंग के माध्यम से ऋण वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जा सके।

अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री गुप्ता ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि कालातीत ऋणी किसानों की सूची सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए। साथ ही जिला सहकारी बैंकों के सीईओ को भी निर्देशित किया कि सहकारी संस्थाओं की अधिक निधियों का विनियोजन केवल सहकारी बैंकों में ही किया जाए, जिससे राज्य की सहकारिता प्रणाली आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बने। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के. एन. कांडे, महाप्रबंधक युगल किशोर, ओएसडी अविनाश श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में

JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131

अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

83वें गोल्डन ग्लोब में अवॉर्ड प्रेजेंट करेंगी प्रियंका

रविवार 11 जनवरी को लास एंजिल्स में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में अब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटेटर्स में शामिल हो गई हैं। आयोजकों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। जिसके बाद जाहिर है कि प्रियंका भी इस अवॉर्ड फंक्शन में अवॉर्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी।

गोल्डन ग्लोब्स के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, अभिनेता जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ स्टेज पर अवॉर्ड्स प्रेजेंट करेंगी। प्रियंका लंबे समय बाद इस प्रतिष्ठित मंच पर नजर आएंगी। प्रेजेंटर्स की इस स्टार-स्टडेड लिस्ट में कई और बड़े नाम भी शामिल हैं।

11 जनवरी को आयोजित होंगे अवॉर्ड्स

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 11 जनवरी को लॉस एंजिल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित होंगे। इसमें फिल्म, टेलीविजन और पहली बार पॉडकास्ट के क्षेत्र में इस साल शानदार काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। कॉमेडियन निक्की ग्लेजर एक बार फिर अवॉर्ड्स को होस्ट करेंगी।

भारत में देख सकेंगे अवॉर्ड्स

लास एंजिल्स में रविवार 11 जनवरी को शाम 5 बजे होने वाला ये अवॉर्ड्स समारोह भारत में सोमवार 12 जनवरी को सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। अमेरिका में इसे सीबीएस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। गोल्डन ग्लोब्स फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड्स में से एक हैं।

'वाराणसी' में नजर आएंगी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी। काफी बड़े स्तर पर बनाई जा रही इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप, क्या एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद रिश्ते में आई खटास?

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को अक्सर पार्टी, इवेंट्स में खूब साथ देखा गया। इन्होंने खुलकर अपने इश्क का इजहार किया। कुछ वक्त पहले न्यू ईयर वेकेशन मनाने भी दोनों साथ गए। लेकिन अब इनके ब्रेकअप की खबर सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इस ब्रेकअप की वजह सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुई घटना बनी है।

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने ब्रेकअप कर लिया है। इस बात की पुष्टि उनसे जुड़े करीबी सूत्रों ने की है। जबकि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में ब्रेकअप क्यों हुआ, इस बात को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इस ब्रेकअप की असल वजह सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को मान रहे हैं।

कुछ दिन पहले सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में तारा सुतारिया पहुंची थीं, उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी साथ थे। कॉन्सर्ट के दौरान एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को मंच पर बुलाया। इस दौरान दोनों के बीच की बॉन्डिंग ने सभी को हैरान कर दिया। स्टेज पर तारा, एपी ढिल्लों के साथ मंच पर थीं और सिंगर ने उन्हें किस कर लिया। इसके बाद जिस तरह से वीर पहाड़िया का रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ, उसने हंगामा मचा दिया। गौरतलब है कि तारा और वीर ने इसी साल अगस्त में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। इंस्टाग्राम पर भी दोनों साथ में फोटो पोस्ट करते थे। लेकिन अब इनके ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं। जिसके पीछे सोशल मीडिया यूजर्स एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुई घटना को जिम्मेदार मान रहे हैं। वैसे तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुई बातों को वायरल करवाने के पीछे नेगेटिव पीआर को जिम्मेदार माना था।

तारा सुतारिया के करियर फ्रंट को लेकर भी चर्चा में हैं। जल्द ही वह साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी। इस फिल्म से उनका लुक भी सामने आ चुका है। 'टॉक्सिक' 19 मार्च को रिलीज होगी, इसकी टक्कर इसी दिन सिनेमाघरों में आ रही फिल्म 'धुरंधर 2' से है।

शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' का टीजर रिलीज, डेब्यू फिल्म रही थी फ्लॉप

बॉलीवुड में 90 के दशक के हीरो रहे संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने बीते साल 2025 में फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया था और ये फिल्म महाफ्लॉप साबित हुई थी। अब शनाया एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी छाप छोड़ने आ रही हैं और उनकी फिल्म 'तू या मैं' का टीजर आज 9 जनवरी को रिलीज हो गया है। इस फिल्म में शनाया की जोड़ी आदर्श गौरव के साथ जमी है और इस फिल्म को 'विजॉय नांबियार' डायरेक्ट कर रहे हैं।

विजॉय इससे पहले वजीर जैसी शानदार कहानी कह चुके हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी लीड रोल निभाया था। शनाया की बीते साल रिलीज हुई फिल्म आंखों की गुस्ताखियां फ्लॉप रही थी और फिल्म में उनकी जोड़ी विक्रांत मैसी के साथ जमी थी जो लोगों को कोई खास पसंद नहीं आई। अब शनाया और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

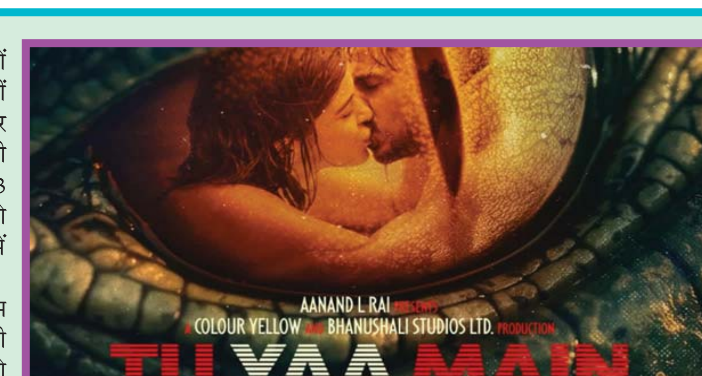

टीजर में फिल्म की कहानी की झलकियां देखने को मिल रही हैं जिसमें आदर्श गौरव एक रैपर के किरदार में दिख रहे हैं। वहीं शनाया कपूर भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही हैं और ग्लैमरस किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म को आनंद एल राय ने प्रोड्यूस किया है जो 'रांझणा' और 'तेरे इश्क में' जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कहानी की ज्यादा डिटेल फिल्म के ट्रेलर के साथ देखने को मिलने वाली है। अब देखना होगा कि क्या शनाया कपूर इस फिल्म से लोगों के बीच अपनी पहचान बना पाती हैं या नहीं।

बता दें कि शनाया कपूर फिल्मी परिवार से आती हैं और उनके पिता संजय कपूर भी अपने समय के हीरो रहे हैं। हालांकि बाद में उनकी फिल्में फ्लॉप रहीं और उन्होंने लीड रोल्स से दूरी बना ली। बीते दिनों मर्डर मुबारक जैसी फिल्मों में हमने संजय कपूर को देखा है लेकिन अब वे खास तरह के किरदारों में ही नजर आते हैं। वहीं अब उनकी बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में अपनी जमीन तलाश रही हैं। हालांकि शनाया की डेब्यू फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' बीते साल रिलीज हुई थी और इस फिल्म में विक्रांत मैसी उनके हीरो रहे थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी और बुरी तरह फ्लॉप रही थी। अब शनाया की ये दूसरी फिल्म है और आदर्शन गौरव के साथ उनकी जोड़ी जमी है। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बड़े पर्दे पर खलेगी विजय की कमी : मालविका

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज फिलहाल टल गई है। 9 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म सेंसर सर्टिफिकेट न मिल पाने के कारण रिलीज नहीं हो सकी। फिल्म का मामला अभी भी मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है। इस बीच अब विजय व 'जन नायकन' के सपोर्ट में तमिल इंडस्ट्री उतर आई है। इस बीच आज ही रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की अभिनेत्री मालविका मोहनन ने थलापति विजय को लेकर बात की है। साथ ही 'जन नायकन' के बाद विजय के फिल्मों से संन्यास लेने पर उन्होंने निराशा जताई है।

इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान मालविका मोहनन ने 'जन नायकन' के बाद विजय के सिनेमा से दूरी बनाने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके सभी प्रशंसकों की तरह मुझे भी बड़े पर्दे पर उनकी कमी खलेगी। उनकी हर फिल्म रिलीज होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। उनकी फिल्म रिलीज से पहले पूरे तमिलनाडु के माहौल में जबरदस्त जोश और उत्साह होता है। इसे महसूस करने के लिए आपको वास्तव में चेन्नई, तमिलनाडु में होना पड़ेगा। बहुत कम अभिनेता अपनी फिल्मों की रिलीज के समय ऐसा माहौल बना पाते हैं।

विजय कभी खुद को सुपरस्टार जैसा नहीं समझते

मालविका ने थलापति विजय के साथ 'मास्टर' फिल्म में काम भी किया है। विजय के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि 'मास्टर' में उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप किसी बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। वह बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और आपकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। वह सचमुच आपके बारे में जानना चाहते हैं। वह लोगों को परखते हैं और उनकी समझ बहुत गहरी है।

इस वजह से टली 'जन नायकन' की रिलीज

एच. विनोथ द्वारा निर्देशित 'जना नायकन' राजनीतिक करियर में कदम रखने से पहले विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी। लेकिन सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसके बाद मेकर्स मद्रास हाईकोर्ट गए, लेकिन अब तक वहां भी फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। इस वजह से फिल्म की रिलीज फिलहाल टल गई है।

'द राजा साब' में नजर आई हैं मालविका मोहनन

मालविका मोहनन प्रभास स्टारर 'द राजा साब' में नजर आई हैं। 'द राजा साब' 9 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस हॉरर-कॉमेफि फिल्म में प्रभास और मालविका के अलावा निधि अग्रवाल, संजय दत्त भी हैं।

खास खबर

सुकमा में उल्लास की लहर, एनसीईआरटी की टीम ने परखा साक्षरता का स्तर

रायपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली की उच्च स्तरीय टीम ने दो दिवसीय बस्तर संभाग प्रवास के दौरान सुकमा जिले में संचालित उल्लास साक्षरता अभियान का गहन मूल्यांकन किया। 08 एवं 09 जनवरी को टीम ने जिले के विभिन्न साक्षरता केंद्रों का दौरा कर जमीनी स्तर पर चल रहे प्रयासों का अवलोकन किया तथा नवसाक्षरों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर बस्तर संभाग के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। टाटा कंसल्टेंसी के किशन गोपाल लड्ढा, उमेन्द्र कटरे एवं एनएसडीसी के प्रतिनिधियों सहित एनसीईआरटी टीम ने सुकमा जिले में साक्षरता के क्षेत्र में प्रशासन की सक्रियता की सराहना की। टीम ने कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के प्रयासों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि जिले में शिक्षा को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। दौरे के दौरान विकासखंड छिंदगढ़ के हमीरगढ़, कुकानार, महिमा, पाकेला तथा सुकमा विकासखंड के पुनर्वास केंद्र मुरतोण्डा का अवलोकन किया गया। विशेष रूप से मुख्यधारा में लौटे नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा पर जोर दिया गया। जिला जेल में संचालित उल्लास केंद्र और साक्षरदूतों की भूमिका को देखकर टीम ने जेल अधीक्षक राजेश बिसेन के प्रयासों की भी प्रशंसा की। इस मूल्यांकन के आधार पर बस्तर संभाग के लिए एक विशिष्ट शैक्षणिक रणनीति तैयार की जाएगी।

सांवरा जनजाति को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ने की अनुकरणीय पहल

रायपुर। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सांवरा जनजाति को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल किया गया। मुंगेली जिला के कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार ग्राम दाऊकापा में विशेष नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 142 सांवरा समुदाय के महिला-पुरुष, बुजुर्ग एवं बच्चों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपचार कराया, इनमें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उच्च रक्तचाप के 12, मोतियाबिंद के 11, दाद-खाज-खुजली के 27, सर्दी-खांसी के 17, बॉडी पेन के 14, मधुमेह के 06, कमजोरी के 13, कान संक्रमण के 06, कुपोषण के 02 मरीज पाए गए। सामान्य रोगियों का मौके पर इलाज किया गया, वहीं गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में ईलाज कराने परामर्श दिया गया। डॉ. मनीष बंजारा ने बताया कि यह शिविर केवल उपचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य, टीकाकरण और सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर आधुनिक चिकित्सा से जोड़ने का संवेदनशील प्रयास किया गया। शिविर की विशेष बात यह रही कि परामर्श स्थानीय भाषा और संवेदनशील संवाद के माध्यम से दिया गया, जिससे लोग बिना डर और झिझक के अपनी समस्याएं साझा करसके। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, गैर-संचारी रोगों की जांच, मौसमी बीमारियों एवं सर्पदंश से बचाव की जानकारी देते हुए नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान समुदाय को टोना-टोटका, झाड़-फूंक से इलाज नहीं कराने, सांप काटने पर तुरंत अस्पताल जाने तथा समय पर टीकाकरण कराने प्रेरित किया गया। शिविर में चिकित्सकगण, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

लोक संस्कृति, जनजातीय गौरव और राष्ट्रबोध का संगम बना आदि लोकोत्सवः मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गोवा के आदर्श ग्राम अमोन, पोंगुइनिम, गोवा में आयोजित 'आदि लोकोत्सव' पर्व 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लोकोत्सव को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में गोवा के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 'आदि लोकोत्सव' के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह लोकोत्सव देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक जीवंत उत्सव है, जो भारत की लोक-सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत गांवों का देश है और गांव हमारी आत्मा हैं। गांवों की संस्कृति ही देश की संस्कृति है, जिसे लोकगीतों, लोकनृत्यों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और परंपराओं के माध्यम से जीवंत रखना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गोवा सरकार पिछले 25 वर्षों से इस सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने का कार्य कर रही है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में आदि लोकोत्सव और भी भव्य तथा व्यापक स्वरूप में आयोजित होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि जनजातीय इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने महज 25 वर्ष की अल्पायु में अंग्रेजों को चुनौती दी और अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अनेक महापुरुष ऐसे हैं, जिन्हें देश के इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय सेनानियों को देशभर में सम्मान और पहचान दिलाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रानी दुर्गावती के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि वे जनजातीय समाज की महान वीरांगना थीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनके गौरव को स्थायी स्वरूप देते हुए मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक भव्य संग्रहालय का निर्माण कराया है, जो उनके शौर्य और बलिदान की अमिट स्मृति है।

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के जनजातीय सेनानियों के योगदान को विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रतिशत जनजातीय आबादी निवास करती है और यहां के 14 जनजातीय महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधुर, गेंद सिंह जैसे महापुरुषों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। शहीद वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी थी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन जनजातीय नायकों की स्मृति को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक उनके बलिदान की गाथा पहुंचाने के उद्देश्य से नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से हुआ। मुख्यमंत्री साय ने आदि लोकोत्सव में उपस्थित सभी लोगों को छत्तीसगढ़ आकर इस डिजिटल संग्रहालय को देखने का आमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि आज देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के रूप में भी जनजातीय समाज की बेटी सुशोभित हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनना प्रधानमंत्री श्री मोदी की समावेशी सोच का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों का स्मरण किया और कहा कि उनके कार्यकाल में ही पहली बार देश में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके माध्यम से आज 12 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर बजट और योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के पहले कार्यकाल में उन्हें उनके साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जिसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान पहले नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में होती थी, लेकिन आज वह तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और राज्य अब शांति, विकास और निवेश के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जिन क्षेत्रों में पहले निवेश नहीं आते थे, वहां अब उद्योग आ रहे हैं।

नेतृत्व और सेवा भाव का सशक्त मंच बनेगी राष्ट्रीय जंबूरीः मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए जैन का स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पहली बार आयोजित हो रहे पाँच दिवसीय राष्ट्रीय रोवरङ्करेंजर जंबूरी आयोजन के लिए डॉ. अनिल जैन को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और इसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए गौरव का विषय बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. अनिल जैन के सक्षम नेतृत्व में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन छत्तीसगढ़ में आयोजित होना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह जंबूरी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भाव को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी मंच बनेगी। देश के विभिन्न राज्यों से आए रोवर-रेंजरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, सामाजिक और युवा शक्ति का राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रदर्शन होगा।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह जंबूरी न केवल युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना : सुशीला बाई के पक्के मकान का सपना हुआ साकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड नवागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिसदा निवासी सुशीला बाई पूर्व में एक जर्जर कच्चे घर में अपने परिवार सहित कठिन परिस्थितियों के बीच जीवन यापन कर रही थीं। बरसात के दिनों में घर में पानी भर जाना, बच्चों को खुले में रात गुजारने की मजबूरी तथा सुरक्षा और सम्मान का अभाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहा। किंतु वर्ष 2024-25 में जब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास सूची में दर्ज हुआ तो उनके जीवन में आशा की किरण साबित हुई। योजना के अंतर्गत 1.20 लाख की स्वीकृत वित्तीय राशि, साथ ही मनरेगा मजदूरी 21,870 रु तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रु. शौचालय निर्माण के लिए प्रदान किए गए।

सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं तकनीकी अमले के मार्गदर्शन में निर्माण समय सीमा के भीतर पूर्ण हुआ और सुशीला बाई का सपना एक सुंदर, सुरक्षित और पक्के आवास के रूप में साकार हो गया। सुशीला बाई गर्व से कहती हैं अब हमारे बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ता, यह घर हमें सुरक्षा के साथ सम्मान भी देता है।

नीली क्रांति की नई शुरुआत : मछली के साथ झींगा पालन बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर स्थित सुकमा जिला अब कृषि एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन में जिले में पारंपरिक धान खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देशन में सुकमा जिले की पांच ग्राम पंचायतों में झींगा पालन की शुरुआत कर नीली क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भेलवापाल, झापरा, गोंगला, मुरातोंडा एवं गादीरास के कुल 17 तालाबों को झींगा पालन के लिए चयनित किया गया है। कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण देने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र, मुरातोंडा में एक विशेष डेमोंस्ट्रेशन यूनिट की स्थापना भी की गई है। हाल ही में मत्स्य विशेषज्ञ डॉ. संजय सिंह

राठौर, मत्स्य विभाग के डी.एल. कश्यप एवं एनआरएलएम जनपद सुकमा के संयोजक सहित विशेषज्ञ दल ने चयनित तालाबों का निरीक्षण कर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया।

अब तक जिले में कतला, रोहू, ग्रास कार्प एवं पेटला मछलियों का पालन किया जाता रहा है। झींगा पालन से स्थानीय कृषकों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल सुकमा को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दामाखेड़ा में संत समागम मेले की तैयारियों की समीक्षा, चाक चौबंद व्यवस्था हेतु दिये निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा मे 23 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे संत समागम समारोह (माघ मेला) की तैयारी हेतु उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं पंथ श्री प्रकाशमुनि नाम साहब की अध्यक्षता में शुक्रवार को सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा प्रांगण में बैठक सम्पन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने संत समागम समारोह की भव्यता को दृष्टिगत रखते हुए सुविधा, व्यवस्था एवं सुरक्षा की चाक - चौबंद इंतजाम हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

पंथ श्री प्रकाशमुनि नाम साहब ने बताया कि संत समागम समारोह (माघ मेला) 23 जनवरी से माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। इस वर्ष समारोह में 23 जनवरी को नवोदित वंशाचार्य उदितमुनि नाम साहब का चादर तिलक समरोह भी होगा, जिसमें अन्य

प्रान्त एवं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह को प्रतिवर्ष जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है इस वर्ष भी सभी का सहयोग प्राप्त होगा और सफलता पूर्वक यह आयोजन सम्पन्न होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। जिससे अधिक मानव संसाधन एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें और समय पर सभी कार्य पूर्ण करें। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहां से मधुर स्मृति अपने साथ लेकर जाएं। श्री शर्मा ने जिला प्रशासन द्वारा अब तक की गई तैयारियों से संतुष्टि जाहिर करते हुए किसी प्रकार की कमी की कोई गुंजाईश न रखने के निर्देश दिये।

राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आज भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि जंबूरी केवल एक शिविर ही नहीं बल्कि एकता, विविधता, भाईचारा और साझा उद्देश्यों का उत्सव है।

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन, मुख्य राज्य आयुक्त इंदरजीत सिंह खालसा, राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से आए रोवर-रेंजर उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं आसमान में गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह में राज्यपाल एवं अतिथियों द्वारा जंबूरी पत्रिका एवं नए बैज का विमोचन भी किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि स्काउट-गाइड युवाओं को नेतृत्व कौशल, अनुशासन और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज के लिए कम से कम एक सकारात्मक कार्य अवश्य करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। देश में पहली बार आयोजित हो रही यह राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्काउट-गाइड युवाओं को जीवन मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि रोवर-रेंजर देश के वे युवा हैं, जो समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए इस आयोजन को छत्तीसगढ़ और देश के युवाओं के लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर बताया। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन करते हुए भारत स्काउट गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. केके खण्डेलवाल ने ग्राम दुधली में इस प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी आयोजन को एतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्य राज्य आयुक्त इंदरजीत सिंह खालसा ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम अध्याय में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

विभिन्न राज्यों से उपस्थित रोवर एवं रेंजरों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट कर राज्यपाल डेका एवं अतिथियों को सलामी दी गई। इस प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न राज्यों से उपस्थित रोवर रेंजरों ने नैनाभिराम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति से भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छटा बिखेरी।

मत्स्य पालन से आर्थिक समृद्धि की राह : श्रीराम मछुआ सहकारी समिति बनी ग्रामीण सशक्तिकरण की मिसाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम कपुआ में स्थित श्रीराम मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, चंद्रगढ़ी ने शासकीय योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। समिति ने मछली पालन को व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करते हुए उत्पादन में निरंतर वृद्धि की है और वर्तमान में इससे प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की जा रही है।

समिति के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कराए गए, जिससे पूंजी की सुलभता बढ़ी और उत्पादन लागत में कमी आई। इसके साथ ही, सदस्यों को 10 दिवसीय मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप समिति ने लगभग 1.50 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित की, जिससे सदस्यों की आजीविका में सुधार हुआ है।

श्रीराम मछुआ सहकारी समिति ने मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में योजनाबद्ध ढंग से कार्य प्रारंभ किया। इसके फलस्वरूप समिति को टॉर बाँध, दर्री तालाब, मरघट तालाब, पैठू तालाब, डोजर बाँध, पीपरहा तालाब एवं गोठान तालाब सहित कुल 21.087 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य पालन का आबंटन प्राप्त हुआ। आज श्रीराम मछुआ सहकारी समिति न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में है, बल्कि क्षेत्र के अन्य मत्स्य समूहों के लिए एक आदर्श बन गई है।

पारंपरिक पेशे को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और सामूहिक प्रयासों से जोड़कर समिति ने यह सिद्ध किया है कि उचित मार्गदर्शन, योजनाबद्ध कार्यप्रणाली और सामूहिक प्रतिबद्धता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

खास खबर

दस्तावेज देने के एवज में पैसे की मांग, पीड़ित ने तहसील कार्यालय के आगे तख्ती लेकर दिया धरना

बलरामपुर। बलरामपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू और चौकीदार पर दस्तावेज़ देने के एवज में अवैध पैसे मांगने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के सामने तख्ती लेकर धरना दिया। दीपक यादव का आरोप है कि दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए 500 की रिश्वत मांगी गई, जबकि सरकारी फ ीस केवल 10 थी। उनके पास 200 मौजूद थे और बाकी 300 वह अधिकारियों से भीख मांग कर देने के लिए धरने पर बैठे थे। जानकारी के अनुसार, दीपक यादव ने अधिकार अभिलेख सेटलमेंट जैसे दस्तावेज़ निकालने के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया और निर्धारित शुल्क जमा कर तहसील कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि दस्तावेज़ देने के दौरान बाबू शिवनंदन पैकरा ने अतिरिक्त ?500 की मांग की। युवक ने रिश्वत देने से इनकार किया और काम रोक दिए जाने की शिकायत की। भ्रष्टाचार से आहत दीपक यादव ने दोपहर लगभग 12:00 बजे धरना दिया, जो लगभग एक घंटे तक चला। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर लिखा, तहसील कार्यालय में 500 रेट फिक्स है, मेरे पास वीडियो प्रमाण भी हैं। सरकारी फीस 10 है, लेकिन काम के लिए 500 चाहिए। मेरे पास 200 हैं, बाकी 300 राजस्व अधिकारियों से भीख मांग कर देने की बात कही। इस घटना के बाद चौकीदार का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होने पर प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जांच तहसीलदार के माध्यम से की जा रही है और दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग की कार्रवाई, 5.76 बल्क लीटर अवैध देशी मदिरा व स्कूटी जब्त

रायपुर। सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर रायपुर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार में आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। आबकारी टीम द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2026 को ग्राम बाना, थाना आरंग अंतर्गत नवीन प्राथमिक शाला के सामने जांच के दौरान अवैध रूप से मदिरा का धारण एवं परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। जांच में ग्राम बाना, थाना आरंग, जिला रायपुर निवासी उजेंद्र बंजारे के अधिपत्य में पाए गए हीरो डेस्टिनी प्राइम स्कूटी की डिक्की से 32 नग पाव देशी मदिरा मसाला यूनिक, कुल 5.76 बल्क लीटर (अन्य जिला महासमुंद की मदिरा) बरामद की गई। आबकारी विभाग द्वारा मौके से अवैध मदिरा सहित स्कूटी वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कराया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक प्रीति कुशवाहा द्वारा की जा रही है। संपूर्ण कार्रवाई में आरक्षक राकेश दुबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जेईई की परीक्षा देने आया रायगढ़ का छात्र लापता

जगदलपुर। जगदलपुर से रायगढ़ निवासी एक 17 वर्षीय छात्र अंश श्रीवास्तव के लापता हो गया है। छात्र यहां यहां जेईई परीक्षा देने के लिए आया था और अपनी नानी के यहां रूका था। परीक्षा के बाद से उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एसडीआरएफकी टीम द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, अंश श्रीवास्तव पिता अमित श्रीवास्तव जेईई परीक्षा देने के लिए लगभग 15 दिन पहले जगदलपुर आया था। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वह घर से अपनी स्कूटी लेकर निकला, जिसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। परिजनों ने बताया कि अंश ने अपने पिता और मामा को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था।

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : उदंती-सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र में 6 शिकारी गिरफ्तार, तीर-कमान, फदा व जाल बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के परिक्षेत्र कुल्हाड़ीघाट के अंतर्गत ओड़ सर्कल में वन्यजीव अपराध के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग की मुस्तैदी के चलते ग्राम सुनाबेड़ा (ओडिशा) के 02 और ग्राम ओड़ के 04 अभियुक्तों को धर-दबोचा गया है।

पकड़े गए अभियुक्तों के पास से खरगोश पकड़ने के फंदे, तीर-कमान और मछली पकड़ने के जाल जैसे शिकार की सामग्री बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध दो अलग-अलग प्रकरणों में पीओआर. (प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट) दर्ज कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी 06 अभियुक्तों को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद के समक्ष पेश किया गया।

वन विभाग की यह कार्रवाई क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों के हौसले पस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन विभाग द्वारा वनों और वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए गश्त अभियान को और अधिक सशक्त किया गया है ताकि भविष्य में शिकार की ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। वन क्षेत्र में शिकार पर अंकुश लगाने के लिए कठोर गश्तए वनकर्मियों की तैनाती, आधुनिक तकनीक,ड्रोन, ट्रैप कैमरे, का उपयोग, स्थानीय समुदायों को जोड़ना, कड़े कानून और जुर्माने, और जागरूकता अभियान जैसे कदम उठाने चाहिए, खासकर पिकनिक या अन्य गतिविधियों की आड़ में होने वाले अवैध शिकार को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाया गयी है।

वनमंत्री ने दिए हैं सख्त कार्रवाई के निर्देश

राज्य वन क्षेत्र अंतर्गत आ रहे शिकार के मामलों पर अंकुश लगाने व ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जिससे वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण व संवर्धन के निर्देश दिए हैं।

साथ ही किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके फलस्वरूप वनमंत्री कश्यप के नेतृत्व व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कुशल दिशा निर्देश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग द्वारा लगातार एंटी स्नेयर वाक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वन विभाग को लगातार सफलता मिल रही है।

प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचते तीन युवक पकड़ाये

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिले की थाना गोबरानवापारा पुलिस ने थाना क्षेत्रांतर्गत तर्री शमशान घाट पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 710 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्राजेपम जब्त किया है।

बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी एसीसीयू सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी कड़ी में थाना

गोबरानवारा पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत तर्री शमशान घाट पास चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला एवं नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर तुलसी राम लेकाम के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी गोबरानवापारा के नेतृत्व में थाना गोबरानवापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा वाहन को चिन्हांकित किया गया। वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम आशीष निर्मलकर, अरमान अहमद एवं किशोर यादव उर्फपप्पू होना बताया।

टीम के सदस्यों द्वारा तलाशी के दौरान उनके पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्राजेपम रखा होना पाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उक्त प्रतिबंधित टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर आरोपियों द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया गया।

जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 710 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्राजेपम कीमती लगभग 50 हजार रूपये, बिक्री नगदी रकम तथा प्रकरण में प्रयुक्त मारूति स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 08 डब्ल्यू 3107 जुमला कीमती लगभग 3 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

मामले में आशीष निर्मलकर पिता स्व. लक्ष्मी नारायण निर्मलकर उम्र 36 साल निवासी कोष्टापारा धमतरी थाना कोतवाली धमतरी जिला धमतरी, अरमान अहमद पिता स्व. ईमरान अहमद उम्र 19 साल निवासी जोहारपारा बालोद थाना बालोद जिला बालोद तथा किशोर यादव उर्फपप्पू पिता गोपाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी धोबनीपारा कुरूद थाना कुरूद जिला धमतरी को गिरफ्तार किया है।

आबकारी विभाग की कार्रवाईः स्कूटी से डिलीवरी करते अवैध देशी शराब बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5.76 बल्क लीटर देसी मदिरा और एक स्कूटी जब्त किया है। यह कार्रवाई सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता के मार्गदर्शन और कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर की गई। आबकारी विभाग जिला रायपुर की टीम ने 8 जनवरी 2026 को आरंग थाना क्षेत्र में बाना गांव में यह कार्रवाई की है।

जांच के दौरान नवीन प्राथमिक शाला के सामने एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब का परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी की पहचान ग्राम बाना निवासी उजेंद्र बंजारे के रूप में हुई है। उसके कब्जे से हीरो डेस्टिनी प्राइम स्कूटी की डिक्की में रखी 32 पाव देसी मदिरा मसाला यूनीक बरामद की गई। जिसकी कुल मात्रा 5.76 बल्क लीटर है। बरामद शराब अन्य जिला महासमुंद की बताई गई है। आबकारी विभाग ने मौके से अवैध शराब और स्कूटी को जब्त कर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच आबकारी उपनिरीक्षक प्रीति कुशवाहा कर रही हैं, जबकि कार्रवाई में आरक्षक राकेश दुबे की अहम भूमिका रही।

जिले में अवैध धान खरीदी-बिक्री और परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

मोहला। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले में खाद्य विभाग द्वारा अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में खाद्य विभाग की टीम जिसमें सहायक खाद्य अधिकारी आशीष कुमार रामटेके, धरमु राम किरंगे और हेमंत नायक ने मानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान 7 जनवरी को मानपुर सेवा सहकारी समिति में ग्राम उरझे, मानपुर निवासी लोचन सिंह सलामें को अपनी पत्नी सुरजा बाई की ऋण पुस्तिका में अवैध धान बेचते हुए पकड़ा गया। कृषक द्वारा लाई गई धान की जांच करने पर यह पाया गया कि वह अलग-अलग किस्म के धान ला रहे थे। पूछताछ में लोचन सिंह ने स्वीकार किया कि वह गर्मी का धान लेकर आए हैं। जांच के दौरान कुल 209 कट्टा धान जप्त कर समिति मानपुर के सुपुर्द किया गया।

इसी तरह, धान खरीदी केंद्र मानपुर में तेरेगांव के किसान बेदसिंह के टोकन पर सावरगांव निवासी सुरेन्द्र डोंगरे द्वारा दो पिकअप में 140 कट्टा धान बिक्री हेतु लाया गया था। निरीक्षण के दौरान इसे अवैध पाया गया और जप्त कर समिति प्रबंधक को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 140 क्विंटल धान जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण और अनियमित खरीदी-बिक्री पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस दिशा में राजस्व, खाद्य, पुलिस एवं मंडी विभाग संयुक्त रूप से निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं।

जिला खाद्य अधिकारी दिलीप कुमार एवं सहायक खाद्य अधिकारी आशीष कुमार रामटेके ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत रकबे में वास्तविक रूप से उत्पादित धान ही सेवा सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों में विक्रय करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यापारी या कोचियों पंजीकृत रकबे में अवैध धान बेचने का प्रयास करते पाए गए, तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जशपुर पुलिस ने 51 लाख की चोरी का खुलासा, पांच गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। जशपुर पुलिस ने थाना नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम केराडीह, रैनीडांड में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। चोरी का मुख्य कारण आईफोन और नगदी का लालच बताया गया।

घटना के अनुसार, प्रार्थीया सुषमा निकुंज के पुराने घर से लगभग 15 लाख रुपए नगद और सोने की ज्वेलरी सहित कुल 51 लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल चोरी किया गया। चोरी में प्रार्थीया की भतीजी मिनल निकुंज ने अपने बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान और अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी मदद से आरोपियों का पता लगाकर उन्हें

गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी हैं: मिनल निकुंज (21 वर्ष, ग्राम केराडीह रैनीडांड), अनिल प्रधान (25 वर्ष, ग्राम बासनताला), अभिषेक इंद्रवार (28 वर्ष, गोरिया टोली, चौकी मनोरा), लंकेश्वर बड़ाईक (35 वर्ष, ग्राम कोंडरा, जिला गुमला झारखंड) और अलीशा भगत (29 वर्ष, ग्राम बाधर कोना, जशपुर)। जांच में पता चला कि मिनल निकुंज ने अपने बॉयफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ मिलकर अटैची से नकद और आभूषण निकाले और चोरी की रकम से हरियर कार खरीदी तथा पार्टियां मनाई। आरोपियों ने चोरी की रकम और सोने के आभूषण को कई जगह छिपाया और कुछ बेच भी दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हरियर कार, एक सोने का कड़ा, तीन सोने के बिस्किट (100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम), एक मंगलसूत्र, 86,300 रुपए नगद, एक आईफोन और चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 51,82,300 रुपए बताई गई है।

आरोपियों के खिलाफ थाना नारायणपुर में धारा 331(4) और 305(A) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने प्रभावशाली कार्यवाही की। इस अभियान में साइबर सेल जशपुर और थाना नारायणपुर की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस रिमांड और पूछताछ के दौरान चोरी की पूरी रकम और सोने के आभूषण बरामद किए गए।

एसएसपी जशपुर ने बताया कि चोरी के सभी मामलों में पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है और शेष फरार आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

कार में बैठकर चला रहे थे सट्टा, 50 लाख रूपये नगद के साथ चार सटोरिये गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर पुलिस ने कार में बैठकर सट्टा का संचालन करते हुए चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 50 लाख रूपये नगद समेत 02 नग लैपटाप, 10 नग मोबाईल फ ोन पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक, केल्क्यूलेटर जप्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्ति ऑन लाईन सट्टा संचालित कर रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान

जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन को चिन्हांकित किया गया। वाहन के पास जाकर देखने पर वाहन के अंदर 04 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम रितेश गोविंदानी, मोहम्मद अख्तर, विक्रम राजकोरी एवं सागर पिन्जानी होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा ऑनलाईन बैटिंग साईट्स ऑलपैनल डॉट कॉम, पॉवर डॉट कॉम,पॉवर एंड सीएच,क्लासिक एंड सीच99 डॉट कॉम के मास्टर आई.डी./आई.डी. के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा (बैटिंग) संचालित करना पाया गया, साथ ही उनके पास लाखों रूपये नगदी रकम भी था। उक्त संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब देकर पुलिस टीम को लगातार गुमराह किया जा रहा था। चारों आरोपियों से जप्त मोबाईल फोन को चेक करने पर पाया गया कि आरोपी रितेश गोविंदानी एवं सागर पिंजानी ऑनलाईन सट्टा खेलने/खिलाने वालों को अलग-अलग ऑनलाईन बैटिंग साईट का मास्टर आई.डी. कमीशन बेस पर उपलब्ध कराते थे, जिसमें आरोपी मोह. अख्तर एवं विक्रम राजकोरी अन्य ग्राहकों को अलग-अलग ऑनलाईन बैटिंग साईट का आई.डी. कमीशन बेस पर उपलब्ध कराकर सभी चारों आरोपी अवैध रूप से लाभ अर्जित कर रहे थे। जिस पर आरोपी रितेश गोविंदानी, मोह. अख्तर, विक्रम राजकोरी एवं सागर पिन्जानी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 50 लाख 35 हजार रूपये, 02 नग लैपटाप, 10 नग मोबाईल फोन एवं हुंडई टक्सन कार क्रमांक सी जी 04 एन क्यू 7745 जुमला कीमती लगभग 80 लाख रूपये तथा पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, चेक बुक, केल्क्यूलेटर जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, 112(2)बी.एन.एस., 66(सी) आई.टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आई.डी. लेकर ऑनलाईन सट्टा खेलने वाले ग्राहको के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।आरोपी रितेश गोविंदानी पूर्व में थाना गुढ़ियारी से बलवा, थाना तेलीबांधा से सट्टा के प्रकरण में तथा आरोपी विक्रम राजकोरी थाना बेमेतरा से हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़े जाने पर जेल निरूद्ध रह चुके है।

मामले में पुलिस ने रितेश गोविंदानी पिता प्रहलाद गोविंददानी उम्र 32 वर्ष निवासी ए-602 ओम श्री अपार्टमेंट शंकर नगर थाना खम्हारडीह रायपुर, मोह. अख्तर पिता मोह. आरिफउम्र 32 वर्ष निवासी मौदहापारा गली नंबर 02 थाना मौदहापारा जिला रायपुर, विक्रम राजकोरी पिता मोहन राजकोरी उम्र 32 वर्ष निवसी ए-206 वेदा इंटरनेशनल के पीछे सुंदर नगर थाना डी.डी. नगर जिला रायपुर तथा सागर पिंजानी पिता अनुप पिंजानी उम्र 30 वर्ष अश्वनी नगर एकता कैम्पस मकान नंबर 17 थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर को गिरफ्तार किया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950